सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-09 | 7 से 21 मई, 2017 | मुख्य संपादक : कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

सार्थक ढंग से मनाएं महान कार्ल मार्क्स की जयंती की द्वि-शताब्दी

आगामी 5 मई को महान कार्ल मार्क्स की जयन्ती का 200वां वर्ष शुरू हो रहा है। 5 मई 1818 को उनका जन्म जर्मनी देश के त्रियेर शहर में हुआ था। उन्होंने कानून, इतिहास व दर्शन का अध्ययन बोन व बर्लिन विश्वविद्यालय में किया। वे पहले हेगेल के द्वन्द्ववाद से, बाद में लुडविग फायरबाख के भौतिकवाद से प्रभावित हुए थे। 1842 में वे *'राइनिशे जाइटुंग'* अखबार के मुख्य सम्पादक बने। उन्होंने इसमें किसानों के हालात पर भी लेख लिखे। सरकारी सैन्सरशिप के कारण उन्हें इससे इस्तीफा देना पड़ा। 1843 में उनका विवाह उनकी बाल-मित्र जेनी से हुआ। इसी साल वे एक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए पेरिस चले गए। यहीं पर क्रान्तिकारी सरगर्मियों के बीच उनकी मुलाकात सितम्बर 1844 में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई जो जीवन पर्यन्त उनके घनिष्ठ मित्र व सहयोद्धा बने रहे।

1845 में जर्मनी की प्रशियाई सरकार के कहने पर मार्क्स को खतरनाक क्रान्तिकारी बता कर पेरिस से निकाल दिया गया। वहां से वे ब्रसेल्स (बेल्जियम) चले गए। इसी दौरान उन्होंने 'दर्शन की दरिद्रता' नामक पुस्तक प्रकाशित कर प्रूदों की धज्जियां उड़ाकर क्रान्तिकारी हल्कों में हलचल मचा दी। इसमें उन्होंने समाजवाद के बारे में तत्कालीन गलत समझ, भ्रान्त धारणाओं व रुझानों के खिलाफ जोरदार ढंग से संघर्ष कर सर्वहारा समाजवाद अर्थात कम्युनिज्म के सिद्धान्त व कार्यनीति प्रस्तुत करने का ऐतिहासिक कार्य किया।

मार्क्स व एंगेल्स दोनों ही एक गुप्त प्रचारकारी संगठन 'कम्युनिस्ट लीग' में शामिल हो गये। उन्होंने नवम्बर 1847 में लन्दन में हुए इसके दूसरे महासम्मेलन में भाग लिया और इसके निर्णय के अनुसार फरवरी 1848 में 'कम्युनिस्ट घोषणा पत्र' प्रकाशित किया जो दुनिया की विभिन्न भाषाओं में सर्वाधिक प्रकाशित पुस्तिका साबित हुई। लेनिन ने बताया है कि ''इस कृति में नया विश्व दृष्टिकोण, सामाजिक जीवन को अपनी लपेट में लेने वाला सुसंगत भौतिकवाद, विकास की सबसे सर्वांगीण तथा गम्भीर शिक्षा के रूप में द्वन्द्ववाद, वर्ग संघर्ष तथा एक नये कम्युनिस्ट समाज के निर्माता के नाते सर्वहारा वर्ग की विश्व ऐतिहासिक क्रान्तिकारी भूमिका का सिद्धान्त मेधावी स्पष्टता और तेजस्विता के साथ वर्णित है।''

1848 में मार्क्स को बेल्जियम से भी निकाल दिया गया। वे पुनः पेरिस आ गए। फिर वहां से वे कोलोन, जर्मनी आ गये जहां वे 19 मई 1849 तक राइनिशे जाइटुंग के मुख्य सम्पादक रहे। वहां उन पर मुकदमा चलाया गया जिसमें वे बरी तो हो गये परन्तु उन्हें जर्मनी से देश निकाला दे दिया गया। लिहाजा वे लन्दन आ गये जहां वे मृत्यु तक रहे।

मार्क्स व उनका परिवार प्रवासी जीवन के बेहद कठोर हालात व घोर अभाव का शिकार रहा जिसमें उनका एक बेटा व बेटी कुपोषण व बिमारी से मर गये। अगर एंगेल्स से निरन्तर आत्मत्यागपूर्ण आर्थिक सहायता न मिलती रहती तो अभाव की मार से मार्क्स निसन्देह टूट गये होते।

1864 में लन्दन में ऐतिहासिक पहले इन्टरनेशनल 'अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ' की स्थापना हुई। मार्क्स इस संगठन के प्राण थे। विभिन्न देशों के मजदूर आन्दोलन को एकताबद्ध करते हुए और तरह-तरह के गलत सिद्धान्तों से लड़ते हुए मार्क्स ने सर्वहारा संघर्ष की कार्यनीति तय की थी। 1867 में 'पूंजी' के महान ग्रन्थ के प्रथम खण्ड को पूरा किया। 1871 में 'पेरिस कम्यून' की घटना का उन्होंने अत्यन्त गहन, सुलझा हुआ, एक शानदार व कारगर क्रांतिकारी मूल्यांकन किया। इन भीषण संघर्षों के साथ साथ अत्यन्त श्रमसाध्य सैद्धांतिक अध्यवसाय ने मार्क्स के स्वास्थ्य को चौपट कर दिया। उन्होंने अनेक दस्तावेजों व ग्रन्थों की रचना की और 'पूंजी' को पूरा करने का काम जारी रखा लेकिन बिमारी उनके समक्ष बाधा बनकर खड़ी हो गई। 2 दिसम्बर 1881 को उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 14 मार्च 1883 को मार्क्स खुद भी अपनी आराम कुर्सी में सदा सर्वदा के लिए सो गये।

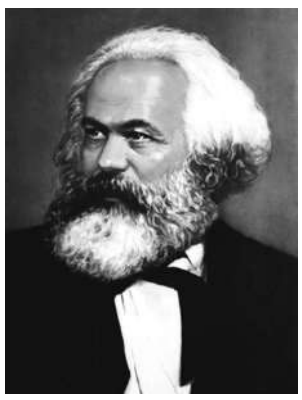

मार्क्स ने दुनिया को द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का वैज्ञानिक दर्शन और वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया जो वर्गों के उन्मूलन की ओर ले जाते हुए राज्य के उन्मूलन अर्थात एक शोषणरहित व शासनरहित स्वतन्त्र व उन्नत कम्युनिस्ट समाज की ओर ले जाता है। पूंजीवादी समाज के सभी अन्तरविरोधों का सुस्पष्ट व सुसंगत विश्लेषण करते हुए उन्होंने समाज के क्रांतिकारी कायापलट के इस ऐतिहासिक व अनिवार्य दौर में चालक शक्ति के रूप में सर्वहारा-मजदूर वर्ग की क्रान्तिकारी भूमिका को निरूपित करते हुए उन्होंने सर्वहारा पार्टी के नेतृत्व व इसकी अग्रणी भूमिका के महत्व को स्पस्ट किया। क्रान्ति के इस संघर्ष में उन्होंने किसान आंदोलनों पर भी ध्यान केन्द्रित कर मूल्यवान शिक्षा प्रदान की। मार्क्स की मृत्यु के उपरान्त महान फ्रेडरिक ऐंगल्स ने बखूबी उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। उनकी सीखों, अनुभवों व संघर्षों को साक्षी रखकर लेनिन के नेतृत्व में रूस की बोल्शेविक पार्टी ने 7 नवम्बर 1917 को प्रथम महान नवम्बर समाजवादी क्रांति सफल कर मार्क्स की भविष्यवाणी को साकार कर दिखाया। यह मार्क्स की 200वीं जयंती के साथ ही महान नवम्बर क्रांति का भी शताब्दी वर्ष है। आइये, प्रथम कम्युनिस्ट शिक्षक, महान कार्ल मार्क्स की सीखों व जीवन संघर्षों को बारीकी से जानें और हमारे देश के क्रान्तिकारी आंदोलन में स्वयं को अपनी जिम्मेदारी निभाने लायक बनायें। 200वीं जयंती के मौके पर आदर के साथ महान कार्ल मार्क्स को याद करें।

देश भर में मनाया गया एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) का 69वां स्थापना दिवस

देश के सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के स्थापना की 69वीं वर्षगांठ देश भर में मनायी गई। जगह-जगह जनसभाएं की गई। कहीं-कहीं पार्टी के किशोर संगठन कॉम्सोमोल द्वारा सलामी परेड की गई। पार्टी के संस्थापक महासचिव, सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कॉमरेड शिवदास घोष के बैज धारण किये गए। सभा स्थल पर कहीं कला, कहीं नवंबर क्रांति की सचित्र प्रदर्शनी व उद्धरण प्रदर्शनी लगाई गई। पार्टी की संगीत मंडली ने क्रान्तिकारी-जनवादी गीत, पार्टी स्थापना दिवस पर रचित गीत, कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय गीत भी प्रस्तुत किया गया। अब तक प्राप्त समाचार यहां प्रकाशित किये जा रहे हैं।

दिल्ली : सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के 69वे स्थापना दिवस पर दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी ने 27 अप्रैल को गांधी शान्ति प्रतिष्ठान सभागार में एक जनसभा का आयोजन किया। दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आये सैंकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों व हमदर्दों ने जनसभा में हिस्सा लिया। सभा की अध्यक्षता पार्टी की दिल्ली राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड प्राण शर्मा ने की। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य एवं एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर साहा थे।

कॉमरेड शंकर साहा ने बताया कि महान लेनिन-स्तालिन के नेतृत्व में किस तरह सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था के तहत पूँजीवाद द्वारा पैदा की गयी तमाम बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंका था। उन्होंने कहा कि आज जब संकटग्रस्त पूँजीवाद-साम्राज्यवाद इतिहास के इन तथ्यों को लोगों से छिपा रहा है तब इन्हें मेहनतकश जनता के सामने प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी क्रान्तिकारी ताकतों की है। मेहनतकश जनता आज पूरी दुनिया में पूँजीवादी शोषण के जुए को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के मद्देनजर एसयूसीआई (सी) महान नवम्बर क्रान्ति का शताब्दी वर्ष मना रही है जिसका उद्घाटन 7 नवम्बर 2016 को दिल्ली के मावलंकर हाल में हुआ था और समापन 17 नवम्बर 2017 को कोलकाता में होगा। कॉमरेड शंकर साहा ने कहा कि महान नवम्बर क्रान्ति का शताब्दी वर्ष मनाना कोई औपचारिकता नहीं है बल्कि रूसी सर्वहारा के क्रान्तिकारी संघर्षों से सबक लेना है जिनकी परिणति महान नवम्बर क्रान्ति में हुई थी जो भारत में पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति की राह रोशन करने में प्रकाश-स्तम्भ का काम करेंगी। क्रान्तिकारी पार्टी एसयूसीआई (सी) को मजबूत करते हुए, इसकी तमाम कमी-खामियों को दूर करके ही इसे हासिल किया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी के अन्दर आलोचना-आत्मालोचना की प्रक्रिया को छेड़ना होगा ताकि पार्टी-पांति में कार्यकताओं के राजनैतिक सांस्कृतिक स्तर को निरन्तर ऊँचा उठाया जा सके और मरणासन्न पूँजीवाद

दिल्ली : सभो को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड शंकर साहा

में क्रान्तिकारियों के घोर शत्रु व्यक्तिवाद के हानिकारक प्रभाव से उन्हें मुक्त कराया जा सके। उन्होंने कॉमरेडों को याद दिलाया कि सीपीएसयू (बोल्शेविक) जैसी एक महान पार्टी भी जिसे लेनिन और स्तालिन ने कष्ट-साध्य संघर्षों से निर्मित और संचालित किया था, वह भी जब मार्क्सवादी-लेनिनवादी रास्ते से भटक गई तो उसे संशोधनवादी

(पृष्ठ 2 का शेष)

24 अप्रैल ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

पार्टी और प्रतिक्रियावादी पार्टी बनने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा। उन्होंने कॉमरेडों से अपील की कि वे हमारे देश की पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति सफल करने के लायक अपने को बनाने के संघर्ष में जुट जायें। हमारे देश की क्रान्ति का प्रभाव पूरी दुनिया के मजदूर वर्ग आन्दोलन को प्रेरित करेगा।

अपने अध्यक्षीय भाषण में कॉ. प्राण शर्मा ने बताया कि किस तरह तमाम पूँजीवादी देशों में फासीवादी रुझान बढ़ रहे हैं और मेहनतकश जनता के जनवादी अधिकारों को पैरों तले रौंदा जा रहा है। इसको रोकने के लिए तमाम वाम व जनवादी ताकतों का संयुक्त आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया।

पटना (बिहार) : 26 अप्रैल को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के स्थापना दिवस पर स्थानीय आई.एम.ए. हाल में राज्यस्तरीय आम सभा की गई। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी की झारखण्ड राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. रबिन समाजपति थे। सभा की अध्यक्षता पार्टी के बिहार राज्य सचिव कॉ. अरुण कुमार सिंह ने की। पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों व हमदर्दों से हाल खचाखच भरा हुआ था।

सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड रबिन समाजपति ने कहा कि देश में जारी आज पूंजीवादी व्यवस्था में सड़न पैदा हो रही है। आज पूंजीवादियों के पास ऐसा कोई उपाय नहीं रह गया है, जिससे वे पूंजीवाद को और टिकाये रख सकें। आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी प्रतिकूल है। आज सोवियत संघ, क्रांतिकारी चीन नहीं है, समाजवादी खेमा नहीं है। आज दुनिया एक ध्रुवीय बन चुकी है। अमेरिका सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन चुका है। वह जो चाहता है, वह करता है। इस स्थिति में हमें एकजुट होकर पूंजीवाद और फासीवाद के खिलाफ संघर्ष तेज करना होगा। और इसके लिए हमें चाहिए एक सही कम्युनिस्ट पार्टी, सही क्रांतिकारी पार्टी। सही क्रांतिकारी पार्टी के लिए सही क्रांतिकारी विचार चाहिए। सही क्रांतिकारी नेतृत्व चाहिए। ऐसा नेतृत्व चाहिए जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद को अपने जीवन में उतार सके। हमारे देश में न तो सीपीआई, न सीपीआई(एम) और न ही सीपीआई(एम-एल) के विभिन्न धड़े ऐसा कर पाये। एकमात्र एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) का निर्माण इस प्रक्रिया में हुआ है। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के निर्माण में सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष तथा उनके मुट्ठीभर साथियों के संघर्षों की चर्चा करते हुए कॉमरेड समाजपति ने कहा कि उस दौरान कॉमरेड शिवदास घोष तथा अन्य नेताओं को न रहने का ठौर-ठिकाना था, न दो जून का पर्याप्त भोजन और न ही पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े। लेकिन इन बातों से परेशान और चिंतित न होकर वे मजदूर वर्ग की एक सही क्रांतिकारी पार्टी के तौर पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष में लगे रहे। उन दिनों सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, बोलशेविक पार्टी, एमसीपीआई आदि पार्टियां काफी ताकतवर थीं। उन पार्टियों के नेता व्यंग्य किया करते थे कि यदि चमगादड़ पक्षी हो सकता है, तो एसयूसीआई भी पार्टी है। लेकिन कॉमरेड शिवदास घोष ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। क्रांति को ही, पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति को ही जनता की मुक्ति का एकमात्र रास्ता बताते हुए कॉमरेड समाजपति ने गर्व के साथ कहा कि हमारी पार्टी में अगली कतार के नेता ही नहीं, बल्कि अनेक समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिनके पास निजी सम्पत्ति नहीं है, जो पार्टी कम्यूनों, सेंटरों और कार्यालयों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी तादाद यानी पेशेवर क्रांतिकारियों की तादाद और बढ़ाने की जरूरत है। यह तादाद जितनी बढ़ेगी, क्रांति उतनी ही नजदीक आयेगी। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) ही सही विचार और नीति-सिद्धांत पर चल रही है। इसके नेता क्रांतिकारी विचार को, मार्क्सवाद-लेनिनवाद को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। शेष तमाम पार्टियां जात-पांत, साम्प्रदायिकता, नीति-सिद्धांतहीनता तथा अवसरवाद की राह पर चलते हुए अंततः पूंजीवाद को ही मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश आज गहरे संकट में है। देश को बचाने की जिम्मेवारी आज सच्चे कम्युनिस्टों पर ही आयद है। सच्चे कम्युनिस्ट ही सच्चे देशभक्त होते हैं। अंत में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे कम्युनिस्ट चरित्र हासिल करने के संघर्ष को तेज करें। जनता के बीच रहें। जन सवालों को लेकर जन कमिटियों का गठन करते हुए जन आंदोलनों का निर्माण करें।

गुना : सभा को संबोधित करते हुए कॉ. धुर्जटी दास

गुना (म.प्र.) : एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पार्टी के स्थापना दिवस हुई सभा का एक दृश्य

सभा की अध्यक्षता करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य सचिव कॉमरेड अरूण कुमार सिंह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र में सत्तासीन भाजपा सरकार जनता से किये गये वायदों को ताक पर रखकर अपने आकाओं-देश के एकाधिकार पूंजीपतियों-के स्वार्थ में आम जन को तंगो-तबाह करने वाले एक के बाद एक कदम उठा रही है। उग्र राष्ट्रवाद, अंध धार्मिक कट्टरता तथा खास तौर पर हिन्दू धार्मिक भावनाएं भड़काकर उग्र अंध प्रतिशोधात्मक साम्प्रदायिक दंगों की ओर देश को धकेलने की पुरजोर साजिश चल रही है। राज्य में सामाजिक न्याय और सुशासन का राग अलापने वाली नीतीश-लालू सरकार केन्द्र में लागू की जा रही जनविरोधी नीतियों का ही अनुसरण कर रही है। शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली में तेजी से बढ़ते निजीकरण की वजह से आम आदमी शिक्षा और स्वास्थ्य से महरूम होता जा रहा है। ठेके पर बहाली, श्रम अधिकारों का घोर उल्लंघन, मजदूर-कर्मचारियों की जायज मांगों की अनसुनी और जन आंदोलनों पर दमन राज्य सरकार के जनविरोधी रवैये को उजागर करते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा आम जन के खिलाफ उठाये जा रहे एक के बाद एक जनविरोधी कदमों का डटकर विरोध करने को वक्त का तकाजा बताते हुए उन्होंने पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं से आह्वान किया वे देश में जारी शोषण, अन्याय, अत्याचार और गैर बराबरी पर आधारित इस पूंजीवादी व्यवस्था को क्रांति की चोट से ध्वस्त कर सही मायने में समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित शोषणविहीन समाज की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ें।

इस मौके पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) उत्तर प्रदेश के सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड स्वप्न चटर्जी समेत राज्य कमिटी के सदस्य भी मंच पर मौजूद थे।

गुना (म.प्र.) : एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी द्वारा पार्टी स्थापना दिवस पर 24 अप्रैल को यहां पर एक प्रदेश स्तरीय जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 1500 से अधिक लोगों ने शिरकत की।

मुख्य वक्ता के रूप में बात रखते हुए पार्टी के केंद्रीय स्टाफ सदस्य कॉमरेड धुर्जटी दास ने कहा कि कम्युनिस्ट नामधारी पार्टियों के रहते हुए भी कामरेड शिवदास घोष द्वारा एसयूसीआई(सी) के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने दिखाया कि जब मार्क्स ने मजदूर राज कायम करने की बात की तब दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाया कि अनपढ़-गवार मजदूर कैसे किसी देश में शासन कर सकते हैं? तब लेनिन के नेतृत्व में रूस में मार्क्सवाद के आधार पर ही क्रांति हुई। लेनिन के अधिक समय जीवित न रह पाने के बाद भी उनके सुयोग्य शिष्य स्टालिन ने जिस प्रकार समाजवाद को सही रूप में स्थापित करके दिखाया उन्होने मार्क्सवाद को एक विज्ञान के रूप में अधिक सुदृढ़ किया।

उन्होंने कहा कि जो लोग यह आरोप लगाते हैं की कम्युनिस्ट देशभक्त नहीं होते उन्हें याद रखना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब एक एक करके यूरोप के सारे देश हिटलर के सामने धराशायी होते जा रहे थे उस समय वे समाजवादी रूस के कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने न केवल अपनी जान देकर अपने देश की रक्षा की बल्कि बर्लिन तक जाकर हिटलर को परास्त करके पूरी दुनिया को फासीवादी ताकतों के आतंक से बचाया था।

उन्होंने दिखाया कि सीपीआई ने किस प्रकार फासीवाद-विरोधी साझा मोर्चा बनाने के सोवियत संघ के नारे को भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषित न कर पाने के चलते साम्राज्यवादी ब्रिटेन का विरोध न करके आजादी आंदोलन के विपरीत कार्य किया था, वहीं आरएसएस के सरसंघसंचालक गोलवलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़कर अपनी उर्जा बर्बाद करने की बजाय मुसलमानों और ईसाइयों से लड़ने की अपील कर आजादी आंदोलन से गद्दारी की थी। उन्होंने दिखाया कि हर तरह से एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) ही एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी है जो देश की जनता को शोषण-उत्पीड़न से मुक्ति दिला सकती है।

एसयूसीआई(सी) के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने अपने सम्बोधन में कहा कि भारतीय पूंजीपति वर्ग अपने व्यापारिक हित के लिए विज्ञान का इस्तेमाल हर तरह से करता है लेकिन बेरोजगारी, भुखमरी और तमाम सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के एकमात्र विज्ञान सम्मत मार्क्सवाद को विदेशी बता कर जनता को गुमराह करके उससे दूर रखता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रदेश की जनता भुखमरी, कंगाली, बदहाली और बेरोजगारी की शिकार है और किस प्रकार प्रदेश सरकार शराब और नशे को बेतहाशा बढ़ावा देकर नौजवानों को भ्रष्ट कर रही है ताकि कोई जन आंदोलन खड़ा ना हो सके। ऐसे में जन आंदोलन गठित कर पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति और तत्पश्चात समाजवाद की स्थापना ही एकमात्र हल है।

सभा में अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन की राज्य सचिव रचना अग्रवाल द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव में कहा गया कि आंदोलन के प्रभाव से प्रदेश भर में महिलाओं के स्वतःस्फूर्त आंदोलन फूट पड़ रहे हैं प्रदेश में जनता हर तरफ शराब बंद करने की मांग उठा रही है।

एआईकेकेएमएस के राज्य सचिव कॉ. मनीष श्रीवास्तव द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव में दिखाया गया कि किसानों की समस्याएं प्रदेश में विकराल रूप धारण करती जा रही हैं और सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के चलते खाद, बीज, कीटनाशक, बिजली और डीजल महंगे होने और किसान की उपज के वाजिब दाम न मिलने के कारण प्रदेश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मार्क्सवाद-लेनिनवाद कॉमरेड शिवदास घोष के चिंतन के आधार पर जोरदार किसान

(पृष्ठ 5 का शेष)

पटना : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. रबिन समाजपति

महान नवम्बर क्रान्ति के सौ साल

(गतांक से आगे)

प्राग पार्टी कान्फ्रेंस (1912) और बोल्शेविकों की अलग मार्क्सवादी पार्टी का गठन

विसर्जनवादियों के खिलाफ संघर्ष की विजय के लिए और मजदूर वर्ग की शक्ति समावेश का काम खत्म कर क्रान्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते जाने के लिए लेनिन के नेतृत्व में प्राग कान्फ्रेंस का फैसला लिया गया।

स्तोलिपिन प्रतिक्रिया के युग में मेन्शेविकों ने जो गद्दारी की थी उसके बाद भी उनके साथ आइन्दा एक ही पार्टी में रहने का सवाल ही नहीं उठता था। नतीजतन, मेन्शेविकों के साथ विच्छेद का फैसला लेने और समस्त बोल्शेविक मतावलम्बियों को एक पार्टी में एकजुट करने की जरूरत थी। इस उद्देश्य से 1912 के जनवरी महीने में प्राग में छठी अखिल रूसी पार्टी कान्फ्रेंस का अधिवेशन शुरू हुआ था। इस अधिवेशन में पार्टी से मेन्शेविकों को निकाल बाहर करने का फैसला लिया गया और बोल्शेविक एक अलग पार्टी के रूप में उभर कर आये।

1912 में प्राग कान्फ्रेंस के नतीजों के प्रसंग में कॉमरेड लेनिन ने गोर्की को लिखा था, "विसर्जनवादी मैल के बावजूद, पार्टी और उसकी केन्द्रीय कमेटी को पुनः प्रतिष्ठित करने में आखिर हम सफल हो गए।" (स. र., 29, पृ.19)

प्राग कान्फ्रेंस के महत्व के बारे में स्तालिन ने कहा था, "हमारी पार्टी के इतिहास में यह कान्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने बोल्शेविकों और मेन्शेविकों के बीच सीमा-रेखाएं खींच दी थी और देश भर के बोल्शेविक संगठनों को एक संयुक्त बोल्शेविक पार्टी में सूत्रबद्ध कर दिया था।"(सीपीएसयू की 15वीं कांग्रेस के आक्षरिक विवरण, पृ. 361-62)

विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि इस प्राग कान्फ्रेंस में कॉमरेड स्तालिन उपस्थित नहीं हो सके थे। वे उस समय निर्वासित थे। लेकिन इसी कांग्रेस में कॉमरेड स्तालिन पहली बार केन्द्रीय कमेटी सदस्य चुने गये थे। रूस के अन्दर पार्टी के कामकाज के संचालन के लिए एक ब्यूरो गठित हुआ था। इस ब्यूरो की जिम्मेदारी कॉमरेड लेनिन ने कॉमरेड स्तालिन को सौंपी थी।

प्रथम साम्राज्वादी युद्ध के समय बोल्शेविक पार्टी की भूमिका और फरवरी क्रान्ति

स्तोलिपिन प्रतिक्रिया के युग में लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने इस ढंग से क्रान्तिकारी आन्दोलन की प्राणसत्ता की रक्षा की थी और मार्क्सवाद के महत्व और श्रेष्ठता को बुलन्द करते हुए मजदूर वर्ग के आन्दोलन को सही दिशा दिखाई थी। महान लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी की इस सिद्धान्तनिष्ठ भूमिका के कारण धीरे-धीरे मजदूर आन्दोलन में फिर प्राण संचार हुआ था और 1912 में फिर समग्र रूस भर में मजदूर आन्दोलन की लहर फैलने लगी थी। क्रान्तिकारी सेन्ट पिटर्सबर्ग के बहादुर सर्वहाराओं का दल मजदूर आन्दोलन की अगली कतार में था। 1914 के प्रथम चरण में हड़ताली मजदूरों की संख्या 15 लाख जा पहुँची थी। इस तरह 1912-14 के हड़ताल आन्दोलन के फैलाव ने देश में जो हालात पैदा कर दिये थे वे 1905 की क्रान्ति के शुरू होने के समय जैसे थे।

इस मजदूर आन्दोलन को वैचारिक तौर पर रास्ता दिखाने के लिए मई 1912 को *'प्रावदा'* (सच्चाई) अखबार प्रकाशित हुआ था। *'प्रावदा'* ने बोल्शेविक पार्टी के गैर-कानूनी केन्द्रों के इर्द-गिर्द कानूनी संगठनों को लामबन्द कर दिया था और एक सुनिर्दिष्ट लक्ष्य की ओर, क्रान्ति की पहलकदमी की ओर मजदूर वर्ग के आन्दोलन को संचालित कर दिया था। बाद में स्तालिन ने कहा था, "1917 की बोल्शेविज्म की जो विजय हुई, उसका सूत्रपात 1912 के *'प्रावदा'* ने किया था।"(हिस्ट्री ऑफ सीपीएसयू (बी), अं, पृ.154)

इस समय ड्यूमा के चुनावों में भी बोल्शेविकों ने बड़ी शिद्दत के साथ भाग लिया था। 1912 में जार सरकार ने चौथी ड्यूमा के लिए चुनावों का निर्देश दिया था। ड्यूमा का बोल्शेविक ग्रुप और *'प्रावदा'* अखबार देशव्यापी कानून से पुनर्जीवित होने के लिए बोल्शेविक पार्टी की क्रान्तिकारी गतिविधियों को चलाने के प्रधान केन्द्र थे। इस तरह लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने गैर-कानूनी और कानूनी–इन दोनों तरह के संगठनों को एक सूत्र में पिरो कर क्रान्ति के गति प्रवाह में ज्वार पैदा करने की कोशिश की थी।

इस समय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना घट गई थी। वह था प्रथम विश्व युद्ध (1914)। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे और दूसरी तरफ थे जर्मनी, आस्ट्रिया और हंगरी। 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था।

जंग शुरू होने से पहले ही लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक समझ गये थे कि साम्राज्यवादी युद्ध अनिवार्य था। युद्ध छिड़ जाने पर देश-देश में समाजवादी किस तरह का कार्यक्रम ग्रहण करेंगे, इस बारे में लेनिन ने अन्तर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में विभिन्न प्रस्ताव पेश किए थे। लेनिन ने दिखाया था कि पूँजीवाद अपने विकास के सर्वोच्च और सबसे आखिरी स्तर–साम्राज्यवाद के स्तर में पहुँच चुका है। इस स्तर में बैंक पूँजी और औद्योगिक पूँजी के विलय के जरिए वित्तीय पूँजी पैदा हो गई है। इस वित्तीय पूँजी को नित नये बाजार और कच्चे माल के स्रोत चाहिएं। विभिन्न देशों की वित्तीय पूँजी अपने बीच विश्व बाजार का बंटवारा कर लेती है। लेकिन इनका विकास असमान रूप से होता है। नतीजतन दुनिया को फिर नये सिरे बांटने की जरूरत दिखाई देती है। इसी जरूरत से शुरू हुआ था 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। सभी देशों के साम्राज्यवादी इस विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थे।

लेनिन ने दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय के नेताओं की ढुलमुल मनोवृत्ति से मजदूर वर्ग को बार-बार आगाह किया था। वे कहा करते थे कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय के नेता केवल मुँह जबानी तौर पर ही युद्ध का विरोध करते हैं। लेकिन युद्ध एक बार जब छिड़ जाता है तो वे अपना मत बदल कर साम्राज्यवादी जंगखोरों के पक्ष में उनका साथ देंगे, युद्ध का समर्थन करेंगे। बाद में लेनिन की यह बात सच साबित हुई थी।

1910 में कोपनहेगन में आयोजित दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय की कांग्रेस में तय हुआ था कि संसद के सोशलिस्ट युद्ध के खर्च के लिए कर्ज के खिलाफ वोट देंगे। 1912 में बाल्कान युद्ध के समय बासले शहर में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय की विश्व कांग्रेस में घोषणा की गई थी कि सभी देशों के मजदूर मानते हैं कि पूँजीपतियों के मुनाफे में बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे को गोलियों से भून डालना घोर अपराध है।

लेकिन साम्राज्यवादियों का विश्व युद्ध जब शुरू हुआ और इन सब प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का समय आया, तब साबित हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय के नेता दगाबाज हैं, वे महज साम्राज्यवाद के ताबेदार हैं। 1914 में 4 अगस्त को जर्मन सोशल डेमोक्रेटों ने संसद में युद्ध-कर्ज को मंजूर किया, साम्राज्यवादी युद्ध के पक्ष में उन्होंने वोट दिया। फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और दूसरे-दूसरे देशों के सोशलिस्टों के एक हिस्से ने युद्ध का समर्थन किया। इन्होंने मजदूरों की आँखों में धूल झोंकने और उनके मन में संकीर्ण अंधराष्ट्रवाद का जहर घोलने में साम्राज्यवादियों की मदद की। समाजवाद से दगाबाजी करने वाले ये लोग पितृभूमि की रक्षा के नाम पर जर्मन मजदूरों को फ्रांसीसी मजदूरों के खिलाफ, अंग्रेज व फ्रांसीसी मजदूरों को जर्मन मजदूरों के खिलाफ उकसाने लगे।

लेनिन के नेतृत्व में सिर्फ बोल्शेविक पार्टी ने ही बिना किसी दुविधा के क्रान्तिकारी तेज के साथ साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ डटकर मोर्चा लेते हुए अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के महान परचम को बुलन्द रखा। अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की धारणा को बुलन्द करते हुए लेनिन ने कहा था : किसी देश का मजदूर वर्ग अगर अपने देश के साम्राज्यवादियों के द्वारा दूसरे देशों को हड़पे जाने के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, तो उस देश का मजदूर वर्ग मुक्ति हासिल नहीं कर सकेगा। लेनिन ने कहा था : अगर आत्म आलोचना के मामले में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय की पार्टियाँ डरी हुई हैं, वे अपनी गलतियों पर पर्दा डालती हैं, भलमानसी का दिखावा करती हैं, क्रान्तिकारी लफ्फाजी के द्वारा अपनी कमी-खामियों और गलतियों को जनता से छिपाती हैं, तो उस देश का मजदूर वर्ग मुक्ति हासिल नहीं कर सकेगा। लेनिन ने कहा था कि ये सब अभ्यास सजीव चिंतन को भोथरा कर देते हैं और अपनी गलतियों से क्रान्तिकारी कोई सीख नहीं ले पाते हैं। आत्म आलोचना के प्रसंग में इस समय लेनिन ने लिखा था, "किसी राजनैतिक पार्टी में कितनी लगन है और अपने वर्ग और मेहनतकश जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों का वह व्यवहार में कैसे पालन करती है–इसे जाँचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक तरीका यह देखना है कि उस पार्टी का स्वयं अपनी गलतियों के प्रति क्या रवैया है। अपनी गलतियों को साफ तौर पर स्वीकार करना, उसके कारणों का पता लगाने, जिन परिस्थितियों में वह गलती हुई हो उनकी छानबीन करना, और उसे सुधारने के उपायों पर पूरी तरह से विचार करना–ये एक गंभीर पार्टी के लक्षण हैं। यही उसका अपना कर्त्तव्य पालन करने का मार्ग है। इसी तरह उसे पहले वर्ग की और फिर जनता की शिक्षा-दीक्षा करनी चाहिए। (सं. र., 31, पृ.-57)

इस समय लेनिन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ–"साम्राज्यवाद–पूँजीवाद की चरम अवस्था" की रचना (1916 में) की थी। साम्राज्यवाद के चरित्र के अनुसार क्रान्ति की राजनीति तय करने के सवाल पर लेनिन ने दिखाया था कि वर्तमान में सर्वहारा वर्ग के लिए बिल्कुल सम्भव है कि वह साम्राज्यवादी मोर्चे को एक या कई जगह तोड़ दे। समाजवाद की जीत पहले कई देशों में, या यहाँ तक कि अकेले एक देश में सम्भव है। लेकिन पूँजीवाद के असमान विकास के कारण सभी देशों में समाजवाद की एक साथ जीत होना असम्भव है। क्रान्ति के बारे में लेनिन के इस नये और पूर्णांग मतवाद को बाद में कॉमरेड स्तालिन ने अपने ग्रंथ 'लेनिनवाद का आधार' में जिस तरह वर्णन किया है, वह यह है, "पहले सर्वहारा क्रान्ति को केवल किसी एक देश के आन्तरिक विकास का ही परिणाम माना जाता था। लेकिन अब यह नजरिया पर्याप्त नहीं रहा। अब सर्वहारा क्रान्ति को प्रधानतया साम्राज्यवाद के विश्वव्यापी मोर्चे के अन्दर चलने वाले आन्तरिक द्वन्द्वों के विकास का परिणाम समझना चाहिए। सच तो यह है कि किसी देश की सर्वहारा क्रान्ति को विश्वव्यापी साम्राज्यवादी मोर्चे की जंजीर के उस देश में टूट जाने का परिणाम मानना चाहिए।

क्रान्ति की शुरूआत कहाँ होगी? कहाँ, किस देश में पूँजी के मोर्चे को सबसे पहले छिन्न-भिन्न किया जा सकेगा?

इस सवाल का जवाब पहले आम तौर पर इस ढंग से दिया जाता था कि–जहाँ उद्योग-धंधे अधिक विकसित होंगे, जहाँ की आबादी में मजदूर वर्ग बहुसंख्यक होंगे, जो देश अधिक संस्कृति सम्पन्न है, जहाँ अधिक जनतंत्र होगा।

लेकिन क्रान्ति का लेनिनवादी सिद्धान्त इस जवाब से सहमत नहीं है। लेनिनवादी कहते हैं : नहीं; कोई जरूरी नहीं है कि क्रान्ति पहले पहल वहीं सफल हो जहाँ उद्योग-धंधे अधिक विकसित हो चुके हैं। बल्कि पूँजी का मोर्चा तो पहले वहाँ टूटेगा जहाँ साम्राज्यवाद की जंजीर की कड़ी सबसे कमजोर है। क्योंकि सर्वहारा क्रान्ति विश्वव्यापी साम्राज्यवादी मोर्चे की जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी के टूटने का ही परिणाम है। इसलिए जिस देश से क्रान्ति शुरू हुई है, जहाँ पर पूँजी का मोर्चा तोड़ दिया गया है, वह हो सकता है कि दूसरे अधिक विकसित देशों की तुलना में पूँजीवादी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो। हो सकता है कि इस पिछड़े हुए देश में क्रान्ति सफल हो जाए और उससे अधिक विकसित देश पूँजीवादी चौखटे में ही कैद रह जाएं।" (सं.र, 6, अं. सं पृ. 99-100)

इसी बीच युद्ध के तीन साल बीत गये। जार की फौज की हार पर हार होती जा रही थी। जर्मन तोपों के गोलों से जार की फौज छिन्न-भिन्न होने लगी थी। जार की फौज के पास न तो गोला-बारूद था और न ही तोप-बन्दूकें। 1916 के दौरान जर्मनी ने समग्र पोलैण्ड और बाल्टिक प्रान्तों के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था।

इसके नतीजतन जार सरकार के खिलाफ मजदूरों, किसानों, सैनिकों और बुद्धिजीवियों की नफरत और गुस्सा सारी हदें पार कर गया था। युद्ध के मैदान में हार के साथ-साथ आर्थिक बदहाली ने भी विकराल रूप ले लिया था। 1917 के जनवरी और फरवरी महीने में खाद्य सामग्री, कच्चे माल और ईंधन की आपूर्ति की अव्यवस्था एकदम चरम पर पहुँच गई थी। पेत्रोग्राद और मास्को में खाद्य सामग्री की आपूर्ति लगभग ठप हो गई थी। कारखानें एक पर एक बन्द होने लगे थे। बेरोजगारी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया था। विशेषकर मजदूरों की दशा असहनीय हो गयी थी। जनता के सामने इस असहनीय परिस्थिति के चंगुल से छुटकारा पाने का एक ही उपाय रह गया था–वह था जारशाही को उखाड़ फेंकना। जनता अपने क्रान्तिकारी कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए आगे आ गई थी।

1917 में 9 जनवरी को पेत्रोग्राद, मास्को, बाकू और निज्नी नोवगोरोड में हड़ताल शुरू हो गई। 18 फरवरी को पुतिलोव कारखाने में हड़ताल शुरू हो गई। 26 फरवरी (11 मार्च) को राजनैतिक हड़ताल और विक्षोभ प्रदर्शन ने अभ्युत्थान का रूप धारण कर लिया। मजदूरों ने पुलिस और फौज के हथियार छीन कर खुद को हथियारबंद करना शुरू कर दिया। 27 फरवरी (12 मार्च) को पेत्रोग्राद में सैनिकों ने मजदूरों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया और विद्रोही जनता के साथ

(शेष पृष्ठ 4 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

आ खड़े हुए। क्रान्ति के पक्ष में सैनिकों को लाने के मामले में महिला मजदूरों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। विद्रोही मजदूरों और सैनिकों ने जार के मंत्रियों और सेनापतियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और जेल से क्रान्तिकारियों को रिहा कर दिया। पेत्रोग्राद में क्रान्ति की विजय की यह खबर दूसरे-दूसरे शहरों और युद्ध क्षेत्रों में फैल गयी और हर जगह मजदूरों और सैनिकों ने जार के कर्मचारियों को पदों से हटा दिया। इस तरह फरवरी महीने में रूस में बुर्जुआ जनतांत्रिक क्रान्ति को विजय प्राप्त हुई।

क्रान्ति शुरू होने के शुरूआती कुछ दिनों में ही सोवियतों का अभ्युदय हो गया। मजदूरों और सैनिकों की सोवियतें विजयी क्रान्ति का सहारा थी। 1905 की क्रान्ति ने साबित कर दिया था कि सोवियतें सशस्त्र क्रान्ति का हथियार हैं और उसके साथ ही नई राज्यसत्ता का भ्रूण भी हैं। फर्क यही था कि 1905 में केवल मजदूर प्रतिनिधियों की ही सोवियतें गठित हुई थी और 1917 की फरवरी में मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतें गठित हो गई थी।

बोल्शेविक जब सड़कों पर उतर कर जनसंघर्ष का संचालन कर रहे थे तब पर्दे की आड़ में मेन्शेविक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी दूसरा ही खेल खेल रहे थे। वे चौथी स्टेट ड्यूमा के उदार बुर्जुआ सदस्यों के साथ एक गुप्त सन्धि में संलिप्त हो गये और उन्होंने रूस में एक नई प्रोविजनल (अस्थायी) सरकार गठित कर ली। इस सरकार के नेतृत्व में थे प्रिंस ल्वोव। इसके अलावा इनमें मिल्यूकोव, गुचकोव, केरैन्स्की भी शामिल थे। इस तरह सोवियत की कार्यनिर्वाहक समिति के सोशलिस्ट और मेन्शेविक नेताओं ने बुर्जुआ वर्ग के हाथों में सत्ता का समर्थन कर दिया था।

लेकिन सवाल उठा कि विजयी मजदूरों और किसानों ने स्वेच्छा से बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता का समर्थन क्यों किया?

इस सवाल के जवाब में लेनिन ने दिखाया, "एक विराट निम्न-पूँजीवादी लहर हर चीज पर छा गई है और उसने न सिर्फ तादाद के पहलू से, बल्कि विचारधारा के पहलू से भी वर्ग सचेत सर्वहारा को मोह लिया है। उसने मजदूरों के बहुत बड़े हिस्से को निम्न-पूँजीवादी राजनैतिक दृष्टिकोण की छूत लगा दी है और उसके मन में यह दृष्टिकोण बिठा दिया है।" (सं. रचनाएं, दूसरा खण्ड पृ.-29)

इस बुर्जुआ सरकार के साथ ही साथ एक और शक्ति दिखायी दी–मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियत। नतीजतन देखा गया था कि दोनों शक्तियों का अद्‌भुत समावेश। अस्थायी सरकार थी बुर्जुआ अधिनायकत्व की प्रतिनिधि और मजदूरों व सैनिकों की सोवियत थी सर्वहारा वर्ग और किसान समुदाय के अधिनायकत्व की प्रतिनिधि। रूस की सरजमीं पर दिखायी दी थी–'दोहरी सत्ता'।

नवम्बर क्रान्ति की तैयारी और इसे सरअंजाम देने में बोल्शेविक पार्टी की भूमिका

1917 में 3 (16) अप्रैल को लेनिन पेत्रोग्राद में आ पहुँचे। फिनलैण्ड रेलवे स्टेशन पर हजारों मजदूर, सैनिक व नाविक उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। एक बख्तरबन्द गाड़ी पर खड़े होकर लेनिन ने दिये अपने प्रसिद्ध भाषण में जनता को समाजवादी क्रान्ति सफल करने का आह्वान किया। 'समाजवादी क्रान्ति जिन्दाबाद' के नारे के साथ उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया।

लेकिन फरवरी क्रान्ति के बाद रूस के सर्वहारा वर्ग का कर्त्तव्य क्या हो –इसको लेकर बोल्शेविक पार्टी में ही तरह-तरह की भ्रम-भ्रान्तियाँ व्याप्त थी। मार्क्सवाद की पुरानी धारणा के अनुसार कई (जो अपने आपको पुराने बोल्शेविक कहा करते थे) यह मानते थे कि सर्वहारा वर्ग का अब काम है बुर्जुआ क्रान्ति को सुदृढ़ करना और बुर्जुआ क्रान्ति के सभी कर्त्तव्य पूरे होने के बाद ही समाजवादी क्रान्ति के लिए संघर्ष किये जायें। इस भ्रांत धारणा के खिलाफ संघर्ष करते हुए लेनिन ने कहा था, "हमारा सिद्धान्त कोई आप्त वाक्य (डॉग्मा) नहीं है बल्कि यह कार्य का मार्गदर्शक है।" (सं. रचनाएं, खण्ड 24, अं.सं पृ. 43)

जारशाही को उखाड़ फेंकने के बाद रूस की परिस्थिति और रूस की क्रान्ति का स्तर विश्लेषण करते हुए लेनिन ने दिखाया था, "तब पहला स्तर क्या होता है? वह है बुर्जुआ वर्ग के हाथों में राज्यसत्ता का चला जाना। ... उसके हाथों में आने से पहले राज्यसत्ता एक पुराने वर्ग के हाथों में थी, वह वर्ग था सामंती भूस्वामी अभिजात वर्ग, जिसका शिरोमणि था निकोलस रोमानोव। क्रान्ति के बाद राज्यसत्ता एक अलग वर्ग; एक नये वर्ग अर्थात् बुर्जुआ वर्ग के हाथों में आ गई है। क्रान्ति शब्द के ठेठ वैज्ञानिक और व्यवहारिक राजनैतिक इन दोनों ही मायनों में किसी क्रान्ति का पहला, प्रधान और मौलिक लक्षण है एक वर्ग के हाथों से दूसरे वर्ग के हाथों में राज्यसत्ता चली जाना। उस हद तक, रूस की बुर्जुआ अथवा बुर्जुआ-जनवादी क्रान्ति पूरी हो गई है।"(सं. रं, 24, पृ. 44)

रूस की क्रान्ति के दूसरे स्तर का चरित्र क्या था? लेनिन ने कहा था, "ग्रामीण अमीरों, कुलकों, मुनाफाखोरों के साथ-साथ पूँजीवाद के खिलाफ मजदूरों, गरीब किसानों, अर्ध सर्वहाराओं और सभी शोषितों को लेकर तथा उस हद तक क्रान्ति समाजवादी है।" (सं. रचनाएं, खण्ड 28 पृ. 300)। लेनिन के इस वक्तव्य का क्या मायने है? इसका मायने है बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति के सामन्तवाद-विरोधी और साम्राज्यवाद-विरोधी काम अगर लगभग सारे के सारे अधूरे रह जायें लेकिन राज्यसत्ता अगर बुर्जुआ वर्ग के हाथों में चली जाये तो भी क्रान्ति का स्तर होगा पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी। लेनिन ने कहा था कि पूँजीवाद के इस साम्राज्यवादी स्तर में बुर्जुआ वर्ग अब जनवादी क्रान्ति के सभी कर्त्तव्य पूरे नहीं कर सकता। बुर्जुआ वर्ग ने आज जनवादी क्रान्ति के झण्डे को धूल में फेंक दिया है। इस परिस्थिति में सर्वहारा वर्ग को राज्यसत्ता पर कब्जा करके बुर्जुआ वर्ग के अधूरे कामों को पूरा करना होगा। यह उसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। बोल्शेविक पार्टी में अब तक जो चिंतनगत भ्रम-भ्रान्ति थी, इस तरह लेनिन ने उसे दूर कर दिया था। इसी समय लेनिन ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने पार्टी का नाम 'सोशल डेमोक्रेटिक' की बजाय 'कम्युनिस्ट पार्टी' रखने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, "हम अपनी पार्टी को अवश्य ही कम्युनिस्ट पार्टी कहेंगे।" (सं. रं, ख 24, पृ. 84) उन्होंने नाम बदलने का सुझाव क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने कहा था, "सोशल डेमोक्रेटिक नाम भ्रामक है। मौजूदा सोशल डेमोक्रेटिक संगठन के नेताओं ने जब समाजवाद को परित्याग दिया है, पितृभूमि की रक्षा के नाम पर वे साम्राज्यवादी लूटेरों की लूट-खसोट का समर्थन कर रहे हैं, अपने-अपने देश के पूँजीपतियों के ताबेदारों में तब्दील हो गये हैं, तब बोल्शेविकों के नाम के साथ 'सोशल डेमोक्रेटिक' लगा रहने से 'जनता गुमराह होगी, उल्टी राह पर चली जायेगी और इस सब नेताओं से ठगी जाती रहेगी।' (सं. र. 24, पृ. 87) लेनिन का यह सुझाव बोल्शेविक सम्मेलन में पारित हो गया।

लेनिन ने कहा था कि सर्वहारा क्रान्ति अगर सर्वहारा की सत्ता को मजबूत करने का मूल कर्त्तव्य पूरा करना चाहती है... तो इस क्रान्ति को सर्वहारा के साथ मेहनतकश और शोषित-पीड़ित लोगों की एक स्थायी मैत्री कायम करनी होगी। इसलिए कायम करनी होगी कि वे मेहनतकश और शोषित-पीड़ित जनता हैं। इस प्रसंग में सोवियतों की भूमिका का वर्णन करते हुए बाद में लेनिन ने कहा था, "भारी तजुर्बों से गुजरते हुए 1905 की रूसी क्रान्ति की जन सृजनात्मक भावना अगर इतने पहले कि फरवरी 1917 में ही सोवियतों को जन्म नहीं दे पाती, तो वह अक्टूबर में सत्ता हरगिज हासिल नहीं कर पाती। क्योंकि सफलता पूरी तरह लाखों लाख लोगों को लेकर आन्दोलन के संगठनात्मक रूप की मौजूदगी पर निर्भर करती थी। संगठन का यह विद्यमान रूप था सोवियतें। इसके फलस्वरूप राजनैतिक क्षेत्र में भावी शानदार कामयाबी हमारी बाट जोह रही थी, लगातार कामयाबी भरा कूंच आगे बढ़ता जा रहा था। इस तरह का तजुर्बा हमें हुआ था। राजनैतिक सत्ता का नया रूप पहले ही हमारे पास तैयार था। हमें जो करना था वह था क्रान्ति के पहले कुछ महीनों से भ्रूण अवस्था में मौजूद सोवियतों की सत्ता को कुछेक डिक्रियाँ जारी करके एक कानून-सम्मत स्वीकृति देना, जो सोवियतों की सत्ता रूसी राज्य कायम हो चुकी है–उसे रूसी सोवियत प्रजातंत्र में रूपान्तरित कर देना।" (सं. र., खं 27 पृ. 89-90)

अगस्त 1917 का उत्तरार्ध था। युद्ध के मैदान में कीचड़ भरी खन्दकों में बैठे लाखों-लाख सैनिक अस्थायी सरकार को कोस रहे थे और दुखी मन से अपने आपसे पूछ रहे थे कि सर्दी का एक और मौसम भी क्या इसी हालत में काटना पड़ेगा? देहात में रात का आकाश विनाशकारी अग्निकाण्ड से आलोकित हो उठा था। सुनने में आ रहे थे भयंकर भयंकर शब्द, खतरे के संकेत। बुर्जुआ अस्थायी सरकार से जमीन पाने की तमाम उम्मीद खोते जा रहे मेहनतकश किसानों के द्वारा अभिजातों के घर-बार जला दिए जा रहे थे, जमीनों पर कब्जे किये जा रहे थे। शहरों में लगातार बढ़ती रफ्तार के साथ लहर पर लहर की तरह फैलती जा रही थी हड़तालें। नयी क्रान्ति आगे बढ़ती जा रही थी। लेनिन ने इस क्रान्ति की भविष्यवाणी की थी। इस क्रान्ति की सम्भावना लेनिन पहले ही देख पाये थे।

जुलाई 1917 में विक्षोभ प्रदर्शन पर गोलियाँ चलाने के बाद लेनिन को भूमिगत होना पड़ा था। वे समझ चुके थे कि बुर्जुआ वर्ग मजदूर-किसानों के खिलाफ गृह युद्ध की तैयारी कर रहा था। इस परिस्थिति में लेनिन ने लिखा था, "तजुर्बा दिखाता है कि गृहयुद्ध है वर्ग संघर्ष का सबसे तीव्रतर रूप। वर्ग संघर्ष में यह वह समय होता है जब आर्थिक–राजनैतिक खटपट और लड़ाइयाँ एक पर एक होती ही रहती हैं, यह विरोध बढ़ते-बढ़ते, व्यापक व तीव्र होते-होते ऐसी मंजिल पर पहुँच जाता है कि वह एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग के सशस्त्र संघर्ष में रूपान्तरित हो जाता है।" (सं. रचनाएं, खण्ड 26, पृ. 29)

विद्रोह को किस तरह विजयी बनाना होगा, इस सवाल पर लेनिन ने लिखा था, "सफलता प्राप्त करने के लिए विद्रोह को षड्यंत्र का और किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि आगे बढ़े हुए वर्ग का अवलंब लेना चाहिए। यह है पहली बात। विद्रोह को जनता की क्रान्तिकारी लहर का अवलंब लेना चाहिए। यह है दूसरी बात। विद्रोह को बढ़ती हुई क्रान्ति के इतिहास में एक ऐसे निर्णायक क्षण का अवलंब लेना चाहिए जब जनता की अपनी पाँतों की सरगर्मियाँ अपने शिखर पर पहुँच गई हों। दुश्मन पक्ष और क्रान्ति के कमजोर, ढीले-ढाले और अदृढ़ मित्रों की पाँतों में भी ढुलमुलपन सबसे ज्यादा हो। यह है तीसरी बात।" (वही, पृ. 22-23) विद्रोह के प्रसंग में कॉमरेड लेनिन ने यह भी लिखा था, "विद्रोह के प्रति मार्क्सवादी रवैया रखने के लिए यानीउसे एक कला मानने के लिए, इसके साथ ही, एक पल का भी समय खोये बिना, हमें विद्रोही टुकड़ियों के एक एक सदर कमान का कर्मचारी-मण्डल संगठित करना चाहिए। अपनी शक्तियों को विभिन्न जगहों पर तैनात कर देना चाहिए। (वही, पृ. 27)

तब देश में शक्ति-संतुलन बदलने लगा था। पेत्रोग्राद और मास्को–इन दोनों राजधानियों में ही बोल्शेविकों ने सोवियतों में बहुमत हासिल कर लिया था। हेलसिंगफार्स में भी सोवियत की सत्ता बोल्शेविकों के हाथों में आ गई थी। पेत्रोग्राद के आस-पास जो सब छोटे-छोटे शहर थे, वहाँ बोल्शेविक और भी सक्रिय हो गये थे। एनस्टर्ड, यूवियेव और रेवाले की सोवियतों ने जुझारू नारा बुलन्द किया था, 'समस्त सत्ता सोवियतों के हाथ में दो।'

इस परिस्थिति में लेनिन ने जोर देकर कहा था कि 'देश में हम ही बहुमत में हैं। दोनों राजधानियों में सावियतें हमारे कब्जे में हैं। हमें ऐसा नारा देना होगा जिससे मेहनतकश जनता का पूरा समर्थन हम निश्चित पा सकें।' लेनिन ने जोर शोर से कहा था कि "विद्रोह में बोल्शेविकों का कामयाब होना अब सुनिश्चित है। पेत्रोग्राद, मास्को और बाल्टिक नौसेना का बेड़ा–इन तीन तरफ से हम अचानक धावा बोल सकते हैं (अगर सोवियतों की कांग्रेस के लिए 'इन्तजार' नहीं करते)।...पेत्रोग्राद में हमारे पास हजारों हथियारबंद मजदूर और सैनिक हैं जो तुरंत शीत महल, फौज के सदर दफ्तर, टेलिफोन एक्सचेंज, सभी बड़े-बड़े छापेखानों को अपने कब्जे में ले सकते हैं। यहाँ से कोई हमें बेदखल नहीं कर सकता। फौज में हम इतने जोर शोर से प्रचार चला सकेंगे कि हमारी शान्ति की सरकार को, किसानों को जमीन देने वाली सरकार से कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा।" (वही, पृ. 83.84)

इसी बीच घटनाक्रम तेजी से विकसित होता जा रहा था। 21 अक्टूबर को लेनिन भूमिगत न रहकर पेत्रोग्राद वापस लौट आये। आते ही कॉमरेड स्तालिन और कॉमरेड स्वेर्दलोव के साथ चर्चा करने बैठ गये। उन्होंने बारीकी से आगामी संघर्ष की तैयारी की खबरें जान ली।

23 अक्टूबर को केन्द्रीय कमेटी का ऐतिहासिक अधिवेशन बैठा। केन्द्रीय कमेटी के कुल 12 सदस्य सभा में मौजूद थे। जुलाई की घटना के बाद यह पहली केन्द्रीय कमेटी की मीटिंग थी जिसमें लेनिन उपस्थित हुए थे। लेनिन ने अपने विचार एक प्रस्ताव के रूप में पेश किये, "सशस्त्र अभ्युत्थान अवश्यम्भावी है और इसके लिए समय बिल्कुल परिपक्व हो गया है, इसके मद्देनजर केन्द्रीय कमेटी सभी पार्टी संगठनों को निर्देश देती है कि इसके अनुसार मार्गदर्शित हों, और इसी के आधार पर सभी व्यावहारिक सवालों को लेकर चर्चा करें और फैसले लें।"(सं. रं, 26 पृ. 190)

लेनिन के इस प्रस्ताव का कामेनेव और जिनोवियेव ने विरोध किया। उन्होंने यह दलील दी कि 'अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। मजदूर वर्ग सक्रिय समर्थन नहीं देगा, देश में हम बहुमत में नहीं हैं, अभी रक्षात्मक रुख अख्तियार

(शेष पृष्ठ 6 पर)

साझे आन्दोलन मजबूत करने के संकल्प के साथ देश भर में मनाया गया मई दिवस

दिल्ली : 1 मई को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर संयुक्त मई दिवस कमेटी की तरफ से यहां रामलीला मैदान से एक भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस पुरानी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों से होता हुआ टाउन हाल पहुच कर सभा में तब्दील हो गया। इसमें सैकड़ों मजदूरों ने शिरकत की। कमेटी में एटक, सीटू, एचएमएस, एआईयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, टीयूसीसी, यूटीयूसी, एमईसी शामिल हैं। सभा को उपरोक्त सभी केन्द्रीय ट्रड यूनियनों के नेताओं ने सम्बोधित किया। एआईयूटीयूसी की ओर से सचिवमण्डल सदस्य कॉमरेड रमेश शर्मा ने सम्बोधित किया।

हरियाणा में रोहतक, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी आदि बहुत सारे जिलों में एआईयूटीयूसी की तरफ से अकेले या संयुक्त प्रदर्शन व सभाएं की गई। **भिवानी** में 1 मई को एआईयूटीयूसी की ओर से नेहरू पार्क में मजदूरों की सभा की गई जिसकी अध्यक्षता एआईयूटीयूसी जिला कमेटी के सह-सचिव कॉ. राजकुमार जांगड़ा ने की, संचालन जिला सचिव कॉ. धर्मवीर सिंह ने किया। सभा के मुख्य वक्ता एआईयूटीयूसी के जिला प्रधान कॉ. रामफल रहे। संदीप, मनोहरलाल, ममता व राजकुमार ने क्रान्तिकारी गीत सुनाये। सभा के बाद शहर में जुलूस निकाला गया।

कॉ. रामफल ने कहा कि 8 घण्टे के कार्यदिवस की मांग पर आन्दोलन का जिक्र आते ही 1886 का शिकागो शहर में हे-मार्केट की घटना याद आ जाती है। उस समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम लिया जाता था। मेहनतकशों ने इन्सानों की तरह जीने के लिए जंग छेड़ी थी। अमेरिकी पूंजीपतियों के बेलगाम हमले से मजदूरों के बहे खून से सड़कें लाल हो गई थी। मालिकों के पक्ष में राजसत्ता का नग्न इस्तेमाल हुआ था। तब जाकर 8 घण्टे के कार्यदिवस को कानूनी मान्यता मिली थी। मई दिवस के संघर्ष के जरिये पूंजीवादी शोषण से मुक्ति की जो चाह व्यक्त हुई थी, वह चाह हमारे देश में आज भी पूरी नहीं हुई है। आज पूंजीवादी भूमण्डलीकरण लागू करके पूंजीपतियों की ताबेदार सरकार द्वारा श्रम कानूनों में मालिकपरस्त संशोधन करके मजदूरों को और भी बंधनों में बांधा जा रहा है। साम्प्रदायिकता फैलाकर मेहनतकशों में फूट डाली जा रही है। उन्होंने पूंजीवादी शोषण-दमन और मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार साझे मजदूर आन्दोलन करने का आह्वान किया।

पानीपत जिले के समालखा में मजदूरों ने जुलस निकाला व सभा की। एआईयूटीयूसी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहाल करने और मारुति के निर्दोष मजदूरों को रिहा करने की मांग की। बेकसूर होते हुए भी 117 मजदूरों को 4 साल जेल में रखने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। वक्ताओं ने कहा कि भले ही यहाँ 8 घण्टे के कार्य दिवस को कानूनी मान्यता मिल चुकी है लेकिन देश-प्रदेश के ज्यादातर उद्योगों व कारखानों में 8 घण्टे का कार्य-दिवस, न्यूनतम वेतन, वेज स्लिप, हाजरी कार्ड, हाजरी रजिस्टर, ई.एस.आई. व पी.एफ. ग्रेच्युटी, पेन्शन जैसे अनिवार्य कानूनी प्रावधान लागू नहीं हैं। जाहिर है कि 1886 में मजदूरों का जितना शोषण किया जाता था आज उससे कहीं ज्यादा शोषण है। उन्होंने न्यूनतम वेतन 18000 रुपये मासिक करने की मांग की।

रेवाड़ी में मई दिवस पर स्थानीय राव तुलाराम पार्क में श्रमिक सभा का आयोजन किया गया। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, आशा, मिड-डे मील, व आंगनवाड़ी कर्मियों, भवन निर्माण मजदूरों आदि ने भाग लिया। सभा की अध्यक्षता अमृतलाल ने की।

सभा के मुख्य वक्ता ऑल इण्डिया यूटीयूसी के प्रांतीय नेता कॉमरेड राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते मजदूर आन्दोलन से प्रदेश की भाजपा सरकार बेचैन हो गई है। वह मजदूर-विरोधी फरमान जारी कर रही है कि 1 मई को मजदूर दिवस न मनाया जाये। पूंजीपतियों की भरोसेलायक पार्टी भाजपा की सरकार की मंशा है कि मजदूर-कर्मचारी मजदूर दिवस से सीख न लें और श्रम अधिकारों का हनन कर दिया जाये। सरकार के इस फरमान की हम भर्त्सना करते हैं। ऑल इण्डिया यूटीयूसी के जिला सचिव कॉ. बलराम, केकेएमएसएस के नेता कॉ. रामकुमार, एमएसएस की नेत्री सन्तोष व सुमन, के अलावा हरिसिंह मुलोधिया, भोजराज आदि ने भी अपने विचार रखे।

कैथल जिले के ढाण्ड कस्बे में 1 मई को भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा सम्बन्धित (एआईयूटीयूसी) के द्वारा मई दिवस पर स्थानीय हरिजन चौपाल मे जनसभा की गई जिसकी अध्यक्षता यूनियन के जिला प्रधान कॉ. नन्दलाल ने की। संचालन कॉ. नरेश कुमार ने किया। कॉ. बाबूराम ने आह्वान किया कि मजदूर आन्दोलन का नेतृत्व सही दिशा व सही हाथों में होना जरूरी है ताकि मजदूर आन्दोलन को अर्थवाद, संसदवाद व कानूनवाद से मुक्त रखा जा सके और कमेरा वर्ग धर्म, जात-पात व इलाके की संकीर्ण मानसिकताओं से मुक्त होकर जीवन से जुड़ी समस्याओं के खिलाफ मजबूत दीर्घस्थायी आन्दोलन गठित करने के लिए आगे आए।

जबलपुर (म.प्र.) 1 मई, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मेहनतकश वर्ग की पार्टी एसयूसीआई (सी) की जबलपुर इकाई ने आज अधारताल लेबर चौक पर अधारताल लेबर चौक से बिरसा मुण्डा चौक तक रैली निकाली। यहां चौक पर स्थित शहीद बिरसा मुण्डा की प्रतिमा पर पुर्ष्पापण किया गया, तत्पश्चात रैली पुन: लेबर चौक आयी। रैली में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इसके बाद सभा आयोजित की गई। सभा को पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव उमाप्रसाद विश्वास ने सम्बोधित किया।

अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि मजदूर ही समाज में हर प्रकार का उत्पादन करता है, लेकिन फिर भी वह जीवन जीने योग्य न्यूनतम सुविधाओं से महरूम रहता है। उन्होंने आगे कहा कि मजदूरों की तमाम समस्याओं की जड़ शोषणमूलक इस पूँजीवादी व्यवस्था में ही निहित है। इसलिए मजदूरों को व्यवस्था परिवर्तन के आन्दोलन में शामिल होना चाहिए।

सभा को एआईयूटीयूसी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कॉ. रूपेश जैन ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में मई दिवस के ऐतिहासिक महत्व को रखते हुए, भवन निर्माण से जुड़े कामगारों की समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया की भवन निर्माण का हितग्राही कार्ड बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि मजदूर हताश होकर अपना कार्ड नहीं बनवा पाता और उसे कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती। इसलिए सरकार द्वारा हितग्राही कार्ड बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू करनी चाहिए। सभा को राधेश्याम, राहुल, वीरा बाई ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पार्टी जबलपुर प्रभारी चन्द्रा पात्रा ने किया।

आरोन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई को दास हनुमान चौराहे पर मजदूरों की सभा की गई। सभा का आयोजन एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए। सभा को पार्टी के स्थानीय प्रभारी कॉ. मनीष श्रीवास्तव ने संबोधित किया।

उधना (गुजरात) : 1 मई को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस शान से मनाया गया। उधना तीन रास्ता पर सायं 4 बजे भारी संख्या में मजदूरों ने इकट्ठा होकर जुलूस निकाला। डिण्डोली जकातनाका, रेलवे क्रासिंग के पास ओवर ब्रिज के नीचे पहुंच कर जुलूस सभा में बदल गया।

सभा के मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी) गुजरात राज्य सचिव कॉमरेड द्वारिकानाथ रथ थे। इसके अलावा राममूर्ति मौर्य, जनरल सेक्रेटरी (साउथ गुजरात टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन) ने भी सभा को सम्बोधित किया।

24 अप्रैल ... (पृष्ठ 2 का शेष)

आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया गया। सभा की अध्यक्षता पार्टी जिला सचिव कॉ. प्रदीप आर. बी. ने की और संचालन कॉ. लोकेश शर्मा द्वारा किया गया।

सभा में बड़ी संख्या में सामाजिक आंदोलनों से जुड़े और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए।

लखनऊ (उ.प्र.) : 24 अप्रैल के दिन राजधानी लखनऊ स्थित गाँधी भवन के संग्रहालय सभागार में उत्तर प्रदेश राज्यस्तरीय आमसभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता और संचालन राज्य सेक्रेटेरियट सदस्यों क्रमश: कॉ. बेचन अली व कॉ. पुष्पेन्द्र ने की। मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी केन्द्रीय स्टाफ सदस्य व बिहार प्रदेश सचिव कॉ. अरुण सिंह ने सभा को संबोधित किया।

अपने भाषण में मुख्य वक्ता ने कहा, ''आज से लगभग 70 साल पहले देश की सरज़मीं पर एक महान मार्क्सवादी चिंतक कॉ. शिवदास घोष ने देश की परिस्थितियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करते हुए महसूस किया कि इस मिट्टी में एक सच्ची मार्क्सवादी पार्टी की सख़्त ज़रूरत है। इसी आलोक में निरीक्षण-परीक्षण करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उस दौर में मौजूद तमाम मार्क्सवादी पार्टियाँ सही मायने में सर्वहारा वर्ग की पार्टी नहीं थीं, अंतत:, उन्होंने कुछ मुट्ठी भर सहयोद्धाओं को साथ लेकर एक मार्क्सवादी पार्टी के गठन के लिए अत्यावश्यक दु:साध्य संघर्ष की शुरुआत की और सन् 1948 में 24 अप्रैल के ही दिन एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की नींव डाली।''

उन्होंने आगे कहा कि आज देश में पूँजीवादी -साम्राज्यवादी शोषण चरम पर है, महँगाई-बेरोज़गारी के

(शेष पृष्ठ 7 पर)

लखनऊ : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड अरुण सिंह

6 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

महान नवम्बर क्रान्ति ...

(पृष्ठ 4 का शेष)

करना ही श्रेयस्कर है, वामपंथी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों को लेकर कन्स्टीट्यूएन्ट असम्बली में हम एक ब्लॉक गठित कर सकते हैं और वहाँ से ही हम अपनी नीतियों को कार्यान्वित कर सकेंगे।' वास्तव में कामेनेव और जिनोवियेव ने क्रान्तिकारी अभ्युत्थान का विरोध करके बुर्जुआ संविधान सभा के पक्ष में वकालत की।

केन्द्रीय कमेटी में से किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया। लेनिन का प्रस्ताव समूची बोल्शेविक पार्टी के लिए हिदायत की तरह चला गया।

केन्द्रीय कमेटी की इस सभा में कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने उन दिनों एक और महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया। विद्रोह के कामकाज के संचालन के लिए एक 'पार्टी सेन्टर' बनाया गया था। इस पार्टी सेन्टर के नेतृत्व में कॉमरेड स्तालिन थे। उनके अलावा थे कॉमरेड स्वेर्दलोव, देर्झिनस्की और ओर्जोनिकड्जे।

केन्द्रीय कमेटी में पराजित हो जाने के बाद कामेनेव और जिनोवियेव ने ऐसा रास्ता लिया जो बोल्शेविक पार्टी के इतिहास में पहले कभी नहीं लिया गया। मेन्शेविक पार्टी की पत्रिका में उन्होंने 1 नवम्बर को क्रान्तिकारी विद्रोह की गोपनीय खबर को खुले आम छाप दिया। मेन्शेविकों की पत्रिका *'नोवाया जीझन'* (नवजीवन) जब लेनिन के हाथों में आई तो उन्हें लगा कि मानो किसी ने जोर से पीठ में छुरा घोंप दिया हो। लेकिन इस विश्वासघात के बावजूद क्रान्ति की जीत के बारे में लेनिन सुनिश्चित थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, "बहुत ही कठिन समय है। सामने कठिन कर्त्तव्य है। गहरा विश्वासघात हुआ है। लेकिन फिर भी हम अपना काम करेंगे ही; मजदूर अपनी पाँतों को मजबूत करेंगे, किसान विद्रोह करेंगे, सरहदों पर सैनिकों का चरम अधैर्य के साथ अपना काम करेंगे! हमें अपनी पाँतों को कसना होगा–सर्वहारा की जीत सुनिश्चित है!"(सं. रं, 26, पृ. 219)

क्रान्ति की तैयारी जब जोर शोर से चल रही थी, तब पहली चोट केरैन्स्की सरकार ने की थी। 6 नवम्बर को प्रतिक्रान्तिकारी फौज की एक टुकड़ी ने आकर बोल्शेविक पार्टी के मुखपत्र *'राबोची पुत'* (मजदूर पथ) की छपाई बन्द करने का हुक्म दिया था। मजदूरों ने हुक्म मानने से इन्कार कर दिया था। हजारों मजदूरों ने आकर प्रतिक्रान्तिकारी कैडेट सैनिकों को घेर लिया था। स्तालिन के निर्देश पर दो बख्तरबन्द गाड़ियों ने आकर सैनिकों को वहाँ से खदेड़ दिया था।

इस हमले की खबर मिलते ही लेनिन ने एक चिट्ठी लिख डाली। उसमें कहा, "कॉमरेड, 6 नवम्बर (पुराने कलैण्डर के मुताबिक 24 अक्तूबर) की शाम को मैं यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। हालात नाजुक हैं और चरम पर पहुँच गये हैं। यह साफ जाहिर है कि अभ्युत्थान यानी विद्रोह में देर हुई तो वह घोर सर्वनाश का कारण हो सकती है। मैं पूरजोर दृढ़ संकल्प के साथ अपने कॉमरेडों को समझाना चाहता हूँ कि अब सब कुछ धागे पर झूल रहा है। ...हर कीमत पर आज शाम को, आज रात को ही सरकार को गिरफ्तार करें, ...हमें इंतजार नहीं करना है, वरना हम सब कुछ खो बैठेंगे ...सरकार लड़खड़ा रही है। हर कीमत पर इसे घातक धक्का देना होगा। देर की तो सर्वनाश हो जाएगा।" (दि हिस्ट्री ऑफ दि सिविल वार इन दि यूएसएसआर, दूसरा खण्ड, पृ. 240)। लेनिन ने जब यह चिट्ठी लिखी, तब स्तालिन ने उनके पास एक संदेशवाहक भेजा, चिट्ठी में लेनिन को स्मोलनी भवन में आ जाने का आमंत्रण था। स्मोलनी भवन जाने के लिए लेनिन फटाफट तैयार हो गये थे। सिर पर टोपी पहन कर एक बड़े रूमाल से चेहरे को ढक कर वे रात के अंधेरे में स्मोलनी भवन की ओर चल पड़े थे।

लेनिन के आने की खबर मिलते ही कुछ कॉमरेडों को साथ लेकर स्तालिन भी वहाँ आ पहुँचे थे। इसी पल से व्यक्तिगत तौर पर लेनिन ने क्रान्तिकारी अभ्युत्थान यानी विद्रोह के संचालन की जिम्मेदारी ले ली थी। क्रान्ति के उन दिनों में स्मोलनी भवन ही उनका निवास स्थान बन गया था। इस स्मोलनी भवन में रह कर ही लेनिन ने शीत महल पर कब्जा करने की अंतिम योजना तैयार की थी।

निर्देश मिलते ही सभी सड़कों पर उतर पड़े। वे उस जगह कतार बाँधे खेड़े हुए थे जहाँ उन्हें हथियार दिये जाने थे। बंदूकों और हथगोलों से लैस होकर मजदूर वाहिनी अपनी निर्दिष्ट जिम्मेदारी निभाने के लिए चल पड़ी थी। मजदूर बस्तियाँ जाग उठी थी। जाहिर था कि इसी शुभ मुहूर्त का वे लम्बे अर्से से इन्तजार कर रहे थे।

पेत्रोग्राद की महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा करने का काम बड़ी तेजी के साथ बड़े अनुशासित ढंग से चल रहा था। रात को एक बज कर पच्चीस मिनट पर जनरल पोस्ट ऑफिस और रात को 2 बजे बाल्टिक रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया। कुछ देर के बाद कब्जे में ले लिया गया टेलिग्राफ ऑफिस। इसके बाद विद्युत केन्द्र और शहर के दूसरी-दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया गया। रात को 3 बजे शीतकालीन महल को घेर लिया गया। प्रोविजनल सरकार के दो मन्त्रियों को गिरफ्तार करके स्मोलनी भवन लाया गया। केन्द्रीय टेलिग्राफ एक्सचेंज पर कब्जा करने का निर्देश भौर के समय 4 बजे आया। इस पर कब्जा करने के बाद शीतकालीन महल के साथ तमाम टेलिफोन सम्पर्क काट दिया गया। सुबह तक शीतकालीन महल की ओर जाने वाले सभी रास्ते क्रान्तिकारी फौज के कब्जे में आ गये थे। सुबह 8 बजे के दौरान क्रान्तिकारी फौज ने वेर्सा स्टेशन पूरी तरह कब्जे में ले लिया। 7 नवम्बर को सुबह ही राजधानी के सभी महत्वपूर्ण केन्द्र क्रान्तिकारियों के कब्जे में आ गये थे।

लेकिन तब तक भी शीतकालीन महल क्रान्तिकारियों के कब्जे में नहीं आया था। क्रान्तिकारी सामरिक कमेटी ने तय किया कि इस बार प्रचण्ड हमला होगा। रात 9 बजे तक अंतिम निर्देश दे दिया गया। अरोरा जहाज से गोले दागने शुरू हो गये। साथ ही साथ अनगिनत बन्दूकें गरज उठी। प्रतिक्रान्तिकारियों का मनोबल बिल्कुल टूट गया। क्रान्तिकारी फौज छोटी-छोटी टुकड़ियों में बंट कर शीतकालीन महल में घुस गई। रात 2 बजे तक बुर्जआ प्रोविजनल सरकार के आखिरी किले शीतकालीन महल का पतन हो गया।

शीतकालीन महल के पतन के साथ-साथ प्रोविजनल सरकार की सत्ता खत्म हो गयी। पेत्रोग्राद में सर्वहारा क्रान्ति विजयी हुई। दुनिया में इससे पहली बार मानव जाति ने एक नये समाज–समाजवादी समाज में प्रवेश किया। सर्वहारा क्रान्तिकारियों का सपना पूरा हो गया।

अगले दिन, 8 नवम्बर को नयी समाजवादी सरकार ने सोवियतों की दूसरी कांग्रेस में दो आज्ञा पत्र (डिक्रियाँ) जारी किये। एक था शान्ति का आज्ञा पत्र, दूसरा था भूमि सम्बन्धी आज्ञा पत्र। नई बोल्शेविक सरकार ने साम्राज्यवादी युद्ध से बाहर निकाल कर युद्ध से तबाह देश में शान्ति कायम करने का काम शुरू किया। इसके साथ-साथ भूस्वामियों के हाथों से जमीन छीन कर किसानों के हाथों में जमीन देने का काम भी शुरू किया गया। लेनिन ने कहा था कि किसानों के हाथों से जमीन छीन लेने की जुर्रत अब कोई नहीं दिखा पायेगा।

पेत्रोग्राद में क्रान्ति की जीत हो जाने पर भी सब जगह लेकिन तब तक भी सत्ता सोवियतों के हाथों में नहीं आ पायी थी। कुछ दिन और मास्को में पथ-पथ पर भयंकर सशस्त्र संघर्ष चला। सत्ता जिससे सोवियतों के हाथों में न जा पाये इसके लिए मेन्शेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ने श्वेत गार्डों और कैडेटों के साथ मिलकर मजदूरों और सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। इसके नतीजतन मास्को में सोवियत शासन कायम करने में और भी कुछ दिन लगे।

क्रान्ति की जीत के बाद पहले कुछ दिनों में ही खास पेत्रोग्राद और दूसरे कुछ इलाकों में सोवियत सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश हुई। केरैन्स्की की पहल पर सेनापति क्रासनोव ने विद्रोह कर दिया। 13 नवम्बर को पुल्कोवा की पहाड़ियों के पास सेनापति क्रासनोव पराजित हुआ। फौज के सदर दफ्तर में प्रधान सेनापति दुखोनिन ने भी विद्रोह करने की कोशिश की। अन्ततः सोवियत सरकार ने जनरल दुखोनिन को भी बर्खास्त कर दिया। इस तरह प्रतिक्रान्ति की विभिन्न छिट-पुट कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। समाजवादी क्रान्ति विजयी हुई।

रूस में समाजवादी क्रान्ति की जीत क्यों हो पायी? क्योंकि लेनिन की प्रज्ञा विशेष परिस्थिति का मार्क्सवाद सम्मत ठोस विश्लेषण कर पायी थी। वे जानते थे कि ठोस परिस्थिति के ठोस विश्लेषण में ही मार्क्सवाद का सार निहित है। (ष्जीम मेमदबम वि डंतगपेउ सपमे पद जीम बवदबतमजम ंदंसलेपे वि जीम बवदबतमजम ेपजनंजपवदण्) इस शिक्षा के अनुसार लेनिन दिखा पाये थे कि साम्राज्यवादी मुल्क आपस में युद्धरत थे–वे एकताबद्ध ढंग से रूसी क्रान्ति के खिलाफ खड़े नहीं हो पाये थे। यहाँ मजदूर वर्ग की सही पार्टी के नेतृत्व में मजदूरों और सैनिकों की सोवियतें निर्मित हो उठी थी और वे लगातार अपनी प्रधानता विस्तार करती जा रही थीं; यहाँ पूँजी और श्रम के बीच समझौतापरस्त ताकतें लगातार जनता से अलग-थलग पड़ती जा रही थीं; रूस की प्रतिक्रियावादी राज्य मशीनरी ताश के पतों के घर की तरह ढहती जा रही थी और बोल्शेविक पार्टी ने जनता की चाहत का अहसास कर शान्ति-जमीन-रोटी का सही नारा जनता के सामने पेश कर दिया था। इसके साथ ही जुड़ा हुआ था रूसी जनता की असीम बहादुरी और कुर्बानी का जज्बा, बोल्शेविक नेता-कार्यकर्ताओं का क्रान्तिकारी तेज और अदम्य मनोबल, बहुसंख्यक मजदूर-किसानों के साथ जीवन्त सम्पर्क स्थापना और उन्हें क्रान्तिकारी शिक्षा से शिक्षित करने की उनकी प्रबल सरगर्मी। इन सबको मिलाकर उन दिनों रूस की सरजमीं पर यह नयी और युगान्तकारी घटना घट पायी थी।

नवम्बर क्रान्ति सफल करने के सवाल पर कॉमरेड लेनिन के योगदान के प्रसंग में कॉमेरड शिवदास घोष ने कहा था, "मजदूरों की पार्टी और नेतृत्व के विषय को लेनिन ने स्पष्ट करके आँखे खोलते हुए दिखाया था और इसकी अपरिहार्यता की बात बार-बार कही थी। ...उन्होंने कहा था कि सही क्रान्तिकारी सिद्धान्त के बिना क्रान्ति नहीं हो सकती। इस सिद्धान्त कहने से उन्होंने सिर्फ एक राजनैतिक और आर्थिक सिद्धान्त को ही नहीं समझाया था बल्कि इससे उनका तात्पर्य था सामूहिक ज्ञान, पार्टी के नेतृत्व का सर्वात्मक ज्ञान।" (सं. र., खण्ड 4, पृ. 299)

"लेनिन ने दिखाया था कि पूँजीवाद के असमान विकास के कारण हर देश के विकास की घटना अलहदा होती है, विशिष्टता भी अलहदा होती है। नतीजतन, स्वाभाविक तौर पर ही मार्क्सवाद के मूल सिद्धान्त का इस्तेमाल भी ब्रिटेन में जिस तरह होगा, उस तरह फ्रांस में नहीं होगा, फिर जर्मनी और रूस में उसका इस्तेमाल अलहदा अलहदा ढंग से होगा।" इसलिए कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था कि मुँह जबानी रट करके मार्क्सवादी- लेनिनवादी तत्व-सिद्धान्त का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस तत्व-सिद्धान्त को इस्तेमाल करना है तो इसे सृजनात्मक ढंग से विकसित करना होगा और एकमात्र तभी इस सिद्धान्त की मर्मवस्तु समझी जा सकेगी। (वही, पृ. 320)

"नवम्बर क्रान्ति के जरिए लेनिन पार्टी, पार्टी नेतृत्व और अॅथोरिटी की धारणा को भी सामने ले आये थे। नेतृत्व का सवाल इतना जरूरी क्यों है? यह क्या पार्टी को अनुशासित-सुचारू ढंग से चलाने के लिए होता है? नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं होता है। बल्कि जनता को सक्रिय भूमिका में खींच लाने के लिए भी नेतृत्व और अॅथोरिटी की जरूरत होती है।" (वही, पृ. 301) इस ढंग से सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष ने नवम्बर क्रान्ति की विभिन्न शिक्षाओं और विचारों को पेश किया था और हमारे देश में और विश्व साम्यवादी आन्दोलन का क्रान्तिकारी संघर्ष गठित करने की राह रोशन की थी।

ब्रेस्त लितोवस्क की सन्धि

8 नवम्बर 1917 को शान्ति का आज्ञा पत्र जारी कर दिये जाने पर भी असल में लेकिन युद्ध बन्द नहीं हुआ। लेकिन टिके रहने के लिए बोल्शेविकों को युद्ध से बाहर निकल आने की जरूरत थी। 24 जनवरी 1918 को बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की एक मीटिंग में लेनिन ने कहा था, "युद्ध में फौज बिल्कुल थककर चूर-चूर हो चुकी है। ...बाल्टिक द्वीप में जर्मनी ऐसी सुविधाजनक स्थिति में खड़ा है कि वे अगर हमला कर दें तो निहत्थे ही रेवेल और पेत्रोग्राद पर कब्जा कर ले सकते हैं। इस स्थिति में युद्ध जारी रखने का मायने है खामख्वाह जर्मन साम्राज्यवाद को मजबूत करना। हमें शान्ति कायम करनी ही होगी। लेकिन देर करने से तो यह शान्ति बहुत ही खराब होगी। क्योंकि यह शान्ति हम कायम नहीं करेंगे। निःसन्देह जिस शान्ति संधि पर दस्तखत करने के लिए हम मजबूर हुए हैं, वह संधि बहुत ही खराब है। लेकिन युद्ध अगर छिड़ता है तो हमारी सरकार उसमें बह जाएगी और शान्ति सन्धि पर दस्तखत फिर कोई दूसरी सरकार ही करेगी। वर्तमान में न केवल सर्वहारा बल्कि गरीब किसान भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। अगर युद्ध चलता रहा तो वे हमारा साथ छोड़ देंगे। ...अपने आपको मजबूत करने के लिए हमें कुछ मोहलत चाहिए।" शान्ति के लिए लेनिन के इस संघर्ष के खिलाफ थे ट्राटस्की, बुखारिन, रादेक और पियाताकोव। साफ-साफ समझा गया कि वे प्रकारान्तर में जर्मन साम्राज्यवाद की ही मदद करना चाह रहे थे। क्योंकि जिस नवजात सोवियत राज्य की उस समय तक भी कोई फौज नहीं थी, उसी को ये जर्मन साम्राज्यवाद के हमले के मुँह में अरक्षित अवस्था में डाल देना चाह रहे थे।

1918 में 10 फरवरी को ब्रेस्त लितोवस्क में शान्ति-वार्ता टूट गयी। पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के नाम पर लेनिन द्वारा शान्ति

(शेष पृष्ठ 7 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति ...

(पृष्ठ 6 का शेष)

संधि करने के लिए निर्देश भेज दिये जाने पर भी ब्रेस्त लिटोवस्क में प्रतिनिधि पार्टी के नेता ट्रॉटस्की ने उसे नामंजूर कर दिया और जर्मनों को जता दिया कि उनकी शर्त रूस नहीं मानेगा, फिर रूस युद्ध भी नहीं करेगा। इस तरह विश्वासघातक ट्रॉटस्की ने रूस के नवजात समाजवाद को जर्मन साम्राज्यवादियों के हमले के मुँह में धकेल दिया। जर्मनी ने 18 फरवरी को फिर रूस पर हमला बोल दिया। उसने पेसकोव और मिनस्क पर कब्जा कर लिया। अन्ततः अत्यन्त कड़ी शर्तों पर रूस की जर्मनी के साथ शान्ति सन्धि पर दस्तखत करने पड़े। रूस को हारना पड़ा सबसे उन्नत प्रांतों का 3 लाख वर्ग मील इलाका, 73 प्रतिशत लौह सम्पदा, 59 प्रतिशत कोयला, 1000 इन्जीनियरिंग कारखाने, 900 कपड़े के कारखाने। 3 मार्च 1918 को सन्धि पर दस्तखत हुए।

देखा गया कि शुरू से ही लेनिन ने अविलम्ब शान्ति सन्धि करने की कोशिश की थी। जर्मनी की पहली शर्त जानने के बाद 1918 में 21 जनवरी को केन्द्रीय कमेटी और तीसरी अखिल रूस सोवियत कांग्रेस के बोल्शेविक प्रतिनिधियों की एक संयुक्त सभा में लेनिन की करारी हार हुई थी। वोट इस प्रकार पड़े थे–अभी हुई सन्धि पर दस्तखत करने के पक्ष में 15 वोट, क्रान्तिकारी युद्ध के पक्ष में 32, युद्ध भी नहीं, सन्धि भी नहीं–इस मत के पक्ष में 16 वोट पड़े थे, यह आखिर में बताया गया मत ही ट्रॉटस्की ने ब्रेस्त लिटोवस्क बातचीत में कार्यान्वित किया था। वस्तुनिष्ठ नीति ग्रहण करने के लिए लेनिन का प्रस्ताव इस प्रकार विभिन्न मीटिंगों में रह-रह कर पांच बार पराजित हुआ। आखिरकार लेनिन का प्रस्ताव 7-4 वोटों से केन्द्रीय कमेटी में गृहीत हुआ। राज्यसत्ता हाथों में लेने के बाद 1918 की 6 मार्च को पार्टी की कांग्रेस आयोजित हुई। इस कांग्रेस में वोट देने के अधिकारी प्रतिनिधियों की संख्या सिर्फ 46 थी। ब्रेस्त लिटोवस्क सन्धि के बारे में लेनिन का प्रस्ताव इस कांग्रेस में पारित हुआ, उनके पक्ष में 30 और विपक्ष में 12 वोट पड़े, 4 व्यक्तियों ने मतदान नहीं किया। अगले दिन लेनिन ने 'एक कष्टपूर्ण सन्धि' लेख में लिखा था, "शांति की शर्तें असहनीय रूप से कठिन हैं। फिर भी, इतिहास का प्राप्य हक उसे मिलेगा ही, ...हमें अब करना चाहिए संगठन, संगठन और फिर संगठन! तमाम विघ्न-बाधाओं के बावजूद भविष्य हमारा है! (सं. र. 27, पृ. 52)

इस तरह ट्रॉस्टकीपंथी छिपे दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए लेनिन देश को साम्राज्यवादी युद्ध से बाहर निकाल लाये, देश को शान्ति और मोहलत दिला दी। इससे लाल फौज तैयार करने के लिए समय मिल गया और पार्टी समाजवाद को मजबूत करने के लिए जुट गई। इन सब कामों में कॉमरेड लेनिन के सहयोद्धा थे कॉमरेड स्तालिन।

(शेष अगले अंक में जारी रहेगा)

पंजीकरण के लिए निर्माण मजदूरों ने किया प्रदर्शन

कैथल (हरियाणा) : 28 मार्च को एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा के बैनर तले मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किया। विक्षुब्ध मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। मजदूर जवाहर पार्क में इकट्ठे हुए। इसके बाद पार्क रोड, पिहोवा चौक, करनाल रोड होते हुए नारे लगाते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन में यूनियन के जिला प्रधान कॉ. नंदलाल, शीशपाल जडौला, जमूठू राम, जगरूप ढाण्ड, नरेश कुमार, संजू पबनावा, भजन सिंह, महावीर कौल भी शामिल थे।

श्रमिक नेताओं ने कहा कि करीब 7 महीनों से निर्माण मजदूरों के नये रजिस्ट्रेशन बंद हैं। प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता के चलते अब तक बहुत सारे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है। वाहवाही लेने के लिए सरकार द्वारा पंजीकृत कापी में 25 योजनाएं छापी गई हैं लेकिन इनमें से अधिकतर कागजों में ही हैं। कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सुविधाओं से भी मजदूरों को वंचित रखा जा रहा है। इससे मजदूरों में रोष व्याप्त है।

दुष्कर्म व छेड़छाड़ के बढ़ते काण्डों के खिलाफ एवं शराबबंदी मांग पर किया प्रदर्शन

हजीरा : 19 अप्रैल को हजीरा चौराहे पर ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया व मॉग की गई की दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दी जाए एवं म.प्र. में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए। सभा में क्षेत्र की महिलाएँ शामिल हुई एवं सभा को राज्य सचिव श्रीमती रचना अग्रवाल ने सम्बोधित किया। उन्होंने आम जनता से अपील की कि शराब हमारे घर, स्वास्थ्य व मानसिकता पर गहरा दुष्प्रभाव डाल रही है। सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर रही है। काफी समय से सरकार जानबूझ कर युवक-युवतियों और लोगों को शराब पिलाने पर आमादा है ताकि उनकी नैतिक रीढ़ टूट जाए और वे रोजगार, बिजली, राशन, शिक्षा, इलाज आदि देने की मांग न करें। सरकार को उनके आकाओं की सेवा करने का मौका मिले। श्रीमती रचना अग्रवाल ने कहा कि जनता को एकजुट होकर इस आन्दोलन को मजबूत करना होगा। संगठन की ग्वालियर जिला सचिव श्रीमती सुचेता सक्सेना ने कहा कि यह आन्दोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि शराबबंदी लागू नहीं हो जाती। सभा को संगठन की जिला उपाधयक्ष मनस्वी व क्षेत्र प्रभारी श्रीमती स्मृति जैन ने भी सम्बोधित किया।

सिकंदर कम्पू : ग्वालियर के एक अन्य क्षेत्र सिकंदर कम्पू में भी रैली का आयोजन किया गया। रैली में क्षेत्र की महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। अंत में रैली सभा में तब्दील हो गई। सभा को क्षेत्र की प्रभारी प्रतिज्ञा मांझी ने सम्बोधित किया।

झारखण्ड में बी.एड छात्र आन्दोलन की राह पर

झारखण्ड में बी.एड छात्र आन्दोलन जारी है। 20 अप्रैल को ऑल इण्डिया डीएसओ द्वारा झारखण्ड के 5 विश्वविद्यालयों में दिन भर विरोध प्रदर्शन किये गए। काल्हान विश्वविालय में ऑल इण्डिया डीएसओ के बैनर तले छात्रों ने एक घण्टे तक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का घेराव किया। भारी पुलिस बल आ पहुंचा लेकिन छात्र टस से मस नहीं हुए। वी सी ने छात्रों से बात करने से इन्कार कर दिया लेकिन एक घण्टे तक घिरे रहने पर अन्ततः वाइस चांसलर छात्रों से मिलने को तैयार हो गए। निश्चित आश्वासन और वायदा मिलने के बाद घेराव खत्म हुआ।

सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन, होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा बढ़ोतरी और शराब की सरकारी दुकानें खोलने के फैसले के खिलाफ रांची में राजभवन पर विशाल प्रदर्शन किया गया। इसका आयोजन एसयूसीआई(सी) की झारखण्ड राज्य कमेटी द्वारा 18 अप्रैल को किया गया।

रांची में राजभवन पर प्रदर्शन करते हुए छात्र

24 अप्रैल ...

(पृष्ठ 5 का शेष)

दिन-ब-दिन बढ़ते बोझ तले दबी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। जनवादी मूल्यों के क्षरण के लिए शासक वर्ग द्वारा लगातार सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है और शोषक वर्ग साम्प्रदायिक राजनीति के ज़रिये पूरे समाज के फासीवादीकरण में पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। आज देश की परिस्थिति माँग करती है कि समस्त जनवाद पसंद व वामपंथी ताकतें एक जोरदार जुझारू जनांदोलन खड़ा करने के लिए आगे आयें और पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति को उसके वांछित अंजाम तक पहुँचायें।

अध्यक्षीय सम्बोधन में कॉ. बेचन अली ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि सभी उपस्थित कार्यकर्ता समाज में कॉ. शिवदास घोष के चिन्तन को प्रसारित व प्रचारित करें और देश के सभी जनवाद-पसंद लोगों को एकजुट करते हुए जीवन के हरेक क्षेत्र में समाजवादी आदर्श की स्थापना के लिए आगे बढ़ें। राज्य सचिव मण्डल के अन्य सदस्यों कॉ. सपन चटर्जी, विजयपाल सिंह, पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा व रविशंकर मौर्य आदि ने भी सभा को सम्बोधित किया।

सरायकेला (झारखण्ड) : 24 अप्रैल को झारखण्ड राज्य के सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में पार्टी स्थापना दिवस पर स्थानीय साई गुरूकुल हाल में हुई सभा की अध्यक्षता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की जिला सचिव कॉ. लिली दास ने की। मुख्य वक्ता के तौर पर झारखण्ड राज्य कमेटी सदस्य कॉ. सुमित राय तथा जिला कमेटी सदस्य आशीष धर उपस्थित थे।

दुर्ग(छ.ग.) : हमारी प्रिय पार्टी एसयूसीआई (सी) के स्थापना दिवस पर 26 अप्रैल को यहां सभा आयोजित की गई जिसमें मुख्स वक्ता के रूप में म.प्र. राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. प्रताप सामल शामिल हुए। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि देश में मजदूर वर्ग व गरीब जनता की पूरी मेहनत से पैदा हुई सम्पत्ति का, धन-दौलत का मालिक पूँजीपति वर्ग है, वही इन सरकारों का मालिक भी है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका काम ही पूँजीपतियों की सेवा करना है। इसी वजह से मजदूर-किसानों, आम लोगों के ऊपर शोषण-जुल्म बढ़ता जा रहा है। हम गरीबों की मुक्ति के लिए क्रान्ति के जरिए पूँजीपति वर्ग को राजसत्ता से हटा कर समाजवाद कायम करना जरूरी है।

उन्होंने रूस की समाजवादी क्रान्ति का उल्लेख करते हुए वहां के समाजवादी समाज में होने वाली प्रगति के बारे में बताया। हमारी पार्टी की स्थापना के इतिहास व उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला। सभा में कॉ. विश्वजीत हारोडे ने भी व्यक्तव्य रखा व अध्यक्षता कॉ. आत्माराम साहु ने की।

रेवाड़ी (हरियाणा) : 24 अप्रैल को स्थानीय पंजाबी धर्मशाला में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया। 24 अप्रैल 1948 को पार्टी की स्थापना महान क्रान्तिकारी नेता कॉमरेड शिवदास घोष ने की थी। हर साल की तरह आज यहां राज्य स्तरीय जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने भागीदारी की। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय कमेटी सदस्य एवं राज्य सचिव कॉमरेड सत्यवान ने की। मुख्य वक्ता केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कामरेड शंकर साहा रहे।

कॉमरेड साहा ने कहा कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्सान के लिए सुनिश्चित, सुरक्षित एवं बेहतरीन जीवन की गारण्टी हो। समाज में आमूल क्रान्तिकारी बदलाव लाने की जरूरत को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि देश के मेहनतकश लोग, मजदूर-किसान जो भी उत्पादन करते हैं वह समाज के लिए करते हैं परन्तु इस पर चन्द पूँजीपतियों का नियंत्रण व मालिकाना होने के चलते लोग भारी शोषण-अन्याय व भेदभाव व उत्पीड़न के शिकार हैं। देश की प्राकृतिक सम्पदा व सामाजिक उत्पादन का सारा लाभ चन्द पूँजीपति ढेर सारे मुनाफे के रूप में हड़प लेते हैं। लोग घोर दरिद्रता व अभाव में जीने पर मजबूर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं, उसकी प्रधान आवश्यक शर्त यह है कि वे अपने खुद के जीवन के रंग-ढंग,

(शेष पृष्ठ 8 पर)

रेवाड़ी : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड शंकर साहा

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Publication : May 5, 2017

सर्वहारा दृष्टिकोण

7 से 21 मई, 2017

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2016 पर कन्वेंशन आयोजित

दरभंगा (बिहार) : नरेन्द्र मोदी–नीत केन्द्र सरकार द्वारा लायी जा रही नई शिक्षा नीति–2016 पर ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमिटी, दरभंगा चैप्टर द्वारा 23 अप्रैल को स्थानीय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (ल.ना.मि. विश्वविद्यालय) के सी. एम. कॉलेज में एक कन्वेन्शन आयोजित किया गया। इसमें अनेक शिक्षकों, प्राध्यापकों, छात्रों और शिक्षा प्रेमी जनों ने गंभीरतापूर्वक भाग लिया।

कन्वेंशन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए प्रख्यात शिक्षाविद् तथा पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक प्रो. विनय कुमार कंठ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2016 शिक्षा के निजीकरण की प्रक्रिया को और तेज करेगी। सरकार शिक्षा की जिम्मेवारी से पूरी तरह मुकरती जा रही है। यह शिक्षा नीति देश में जारी शिक्षा–विरोधी नीतियों में कोई खास बदलाव तो लायेगी ही नहीं, बल्कि बची–खुची शिक्षा भी आम छात्रों की पहुंच से दूर हो जायेगी। इसके साथ ही जनता की सोच को, मानसिकता को नियंत्रित किया जा रहा है। देश में शिक्षा को पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश जारी है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि देश के लोग सरकार की शिक्षा–विरोधी नीतियों का डटकर विरोध कर रहे हैं।

ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमिटी, बिहार चैप्टर के संयोजक राजकुमार चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाली नयी शिक्षा नीति के दस्तावेजों व रिपोर्टों में न तो कहीं शिक्षा के उद्देश्यों का जिक्र है और न ही 'जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा' का। भावी शिक्षा नीति में भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के जरिये चुनिन्दा विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया है। जाहिर है उनकी फीस अत्यधिक और उनके 'ब्रांड वैल्यू' के आधार पर होगी। इसमें न स्कूलों के लचर ढांचे, शिक्षकों व शैक्षिक सामग्रियों की बेहद कमी का जिक्र है और न ही शैक्षिक अनियमितताओं, गड़बड़ियों और धांधलियों के समाधान की कोई दिशा। उन्होंने कहा कि भारत में जीडीपी का 6 प्रतिशत भी कभी शिक्षा पर खर्च नहीं हुआ।

कन्वेंशन को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमिटी, बिहार चैप्टर की पूर्व सचिव साधना मिश्रा ने कहा कि सरकारों द्वारा अत्यंत लापरवाही और प्रयासों की कमी की वजह से आज बुनियादी शिक्षा बदहाली के आंसू बहा रही है। शिक्षा के लिए बजट में आवंटन बढ़ाने की बजाय सभी सरकारों ने शिक्षा बजट में कटौती की है। उन्होंने कहा कि आने वाली शिक्षा नीति में शैक्षिक संस्थानों को राष्ट्रीय बहसों का राजनैतिक केन्द्र न बनाने की चेतावनी देते हुए शैक्षिक संस्थानों में छात्रों की राजनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही गयी है। समाज के संदर्भ में भी न्याय, स्वतंत्रता या समान अवसर की जगह बाजार को तरजीह दी गयी है।

कन्वेंशन की अध्यक्षता करते हुए कमिटी के दरभंगा चैप्टर के अध्यक्ष तथा ल. ना.मि. विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के प्राध्यापक प्रो. धर्मेन्द्र कुमर ने कहा कि किसी भी सभ्य सरकार को शिक्षा की पूरी आर्थिक जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहिए। लेकिन आने वाली शिक्षा नीति में कहा गया है कि उच्च शिक्षा केवल सरकारी खर्च से नहीं चल सकती। शिक्षा क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश और पीपीपी मॉडल को जारी रखने का भी परामर्श दिया गया है। स्पष्ट है कि शिक्षा का अवसर कुछ मुट्ठीभर लोगों तक ही सिमटकर रह जायेगा। उन्होंने आने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ तमाम शिक्षकों, प्राध्यापकों, छात्रों और शिक्षा प्रेमी जनों से एकताबद्ध शिक्षा आंदोलन के निर्माण की अपील की।

कन्वेंशन को ल. ना. मि. विश्वविद्याल के पूर्व छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉ. प्रभु नारायण झा, एम. आर. एम. महिला कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. विद्या नाथ झा, ल. ना.मि. विश्वविद्यालय के भू–सम्पदा पदाधिकारी डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद सुमन, मिथिला शोध संस्थान के प्राचार्य डॉ. मित्रनाथ झा, डॉ. जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, दरभंगा के प्राचार्य डॉ. मंजर सुलेमान, ल. ना.मि. विश्वविद्यालय के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. प्रभास चन्द्र मिश्र, साहित्यकार ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, मध्य विद्यालय नरौरा के शिक्षक रूसो सेनगुप्ता, शिक्षक नेता अमरनाथ ठाकुर व अभिषेक कुमार भगत, छात्र नेता डॉ. सुमन कुमार झा, ललित कुमार झा, अमित कुमार ठाकुर आदि ने भी संबोधित किया।

कन्वेंशन का आधार पत्र कमिटी के दरभंगा चैप्टर के सचिव लाल कुमार ने प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत इसके उपाध्यक्ष डॉ. हीरालाल सहनी ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन मुजाहिद आजम ने किया।

स्कूलों में हिन्दी थोपने के केन्द्र सरकार के फैसले की एसयूसीआई(सी) ने की तीव्र आलोचना

स्कूलों और अन्य अदारों में हिन्दी थोपने के केन्द्रीय सरकार के फैसले की तीव्र आलोचना करते हुए एसयूसीआई (सी) के महामंत्री कॉमरेड प्रभास घोष ने 20 अप्रैल 2017 को निम्नलिखित बयान जारी किया।

तमाम केन्द्रीय व सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 10 तक हिन्दी को अनिवार्य बनाने की संसदीय समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के भारत सरकार के हालिया फैसले की हम तीव्र आलोचना करते हैं, इसी फैसले को कथित तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 31 मार्च को जारी प्रेजिडेंशिल आर्डर में भी उल्लेखित किया गया है। इस कदम का और भी अनिष्टकर पहलू यह है कि इसे सरकारी और सामाजिक गतिविधियों के विभिन्न अन्य अदारों में हिन्दी को वस्तुत: अनिवार्य बनाने की नीयत से किया जा रहा है। यह उच्च शिक्षा में, सिविल सर्विस परीक्षाओं की तैयारी के लिए तैयार की जाने वाली सामग्री में, ब्रोशर और पत्रिकाओं में, एयरलाइंस की टिकटों में या सांसदों द्वारा संसद में दिये जाने वाले भाषणों तक में, यहां तक कि राष्ट्रपति के भाषण में भी हिन्दी को अनिवार्य बनाने के लिए किया जा रहा है।

हमारा यह सुविचारित मत रहा है कि हमारे जैसे बहुभाषी देश में कोई भी भाषा थोपने के जरिए फल–फूल नहीं सकती है क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह स्वैच्छिक होती है। द्वीभाषा फार्मूला लागू किया जाना चाहिए मसलन शिक्षा की पूरी अवधि के दौरान मातृभाषा और अंग्रेजी को सीखना क्योंकि इससे ही शिक्षा के असल उद्देश्य की पूर्ति सबसे बेहतर तरीके से होगी।

भाषा पर इस नीति के सर्वथा विपरीत देशभर में एक विशेष भाषा को थोपने का मौजूदा फैसला देश में बदतरीन किस्म के मतभेदों और विभाजनों के बीज बोने के गम्भीर खतरे से भरा हुआ है। इस बात को कभी भी नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए कि भाषा एक अति संवेदनशील मुद्दा है, किसी भी भाषा को थोपने की तरफ बढ़ाया गया ऐसा एक कदम अविश्वास और फूट पैदा करेगा और प्रभावित लोगों की भावनाओं को गम्भीर रूप से आहत करेगा। यह भाषागत दुराग्रह भी पैदा करेगा जो पहले से ही लोगों की एकता को कमजोर कर रहे विभाजनकारी मनोभावों को और भी हवा देगा।

ऐसी एक स्थिति में भारत के राष्ट्रपति सहित सरकार से हम मांग करते हैं कि केन्द्रीय और सीबीएसई स्कूलों तथा अन्य स्तरों पर सामाजिक और सरकारी गतिविधियों में हिन्दी को अनिवार्य बनाने का यह विनाशकारी फैसला तुरन्त वापस लिया जाए और मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा जाए।

गोरक्षकों को सजा देने की मांग पर दिल्ली में धरने पर बैठी मृतक बेटे की मां

अप्रैल के शुरू में अलवर में 55 वर्षीय पहलू खान स्वघोषित गो–रक्षकों की नृशंसता के शिकार होकर लहूलुहान हालत में हस्पताल में मारे गए थे। पहलू खान व उनके दो बेटों सहित और भी चार किसानों का कसूर यह था कि वे खेती के लिए बैल खरीद कर ला रहे थे। गो–तस्करी का ठप्पा लगा कर स्वघोषित गो–रक्षकों ने उन पर हमला किया। फिर भी प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। काफी समय बीत जाने पर भी अलवर काण्ड के असली अपराधी पकड़े नहीं गए हैं।

अन्तत: दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग पर धरने पर बैठने को मजबूर हुई बेटे को खो बैठी मां अंगूरी बेगम। 19 अप्रैल को जन्तर मंतर पर भूमि अधिकार आन्दोलन के बैनर तले आयोजित धरने पर पहलू खान के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग पर एसयूसीआई(सी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड सत्यवान ने वक्तव्य रखा। गो–रक्षा के नाम पर विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल की साम्प्रदायिक मारकाट के विरोध में राज्य के गणमान्य जनों सहित अनेक लोग मुखर हो रहे हैं। धर्म की आड़ में इन्सान–इन्सान के बीच फूट डालने की इस राजनीति के खिलाफ आज हर तबके के लोग आगे आ रहे हैं।

दिल्ली : जंतर मंतर पर धरने को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सत्यवान

24 अप्रैल ...

(पृष्ठ 7 का शेष)

आदत–आचरण के हर मामले में सांस्कृतिक रूप से बदलाव लायें। तभी शोषण मुक्त समाज बनाना सम्भव होगा। महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष ने ऐसा समाज सृजन के लिए ही क्रान्तिकारी पार्टी– एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बनाई थी और इस पार्टी को ताकतवर बनाने का आह्वान किया था जो नई सामाजिक व्यवस्था को लाने व इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी निभायेगी।

जनसभा के मंच का संचालन एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) रेवाड़ी जिला कमेटी के सचिव कॉमरेड राजेन्द्र सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लम्बे कुशासन के बाद केन्द्र व प्रदेश में आयी भाजपा सरकारें भी ज्यादातर मामलों में पिछली सरकार के जनविरोधी रास्ते पर चल रही हैं।

अध्यक्षीय भाषण में कॉमरेड सत्यवान ने सरकार की जनविरोधी नीतियों व कार्रवाईयों के खिलाफ एक ताकतवर जन आन्दोलन खड़ा करने का आह्वान किया। एक तरफ पहले से प्राप्त अधिकारों व सुविधाओं को छीन कर लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने और दूसरी तरफ भारतीय परम्परा के नाम पर धर्मान्धता, रूढ़िवाद, उग्रराष्ट्रवाद, साम्प्रदायिक व जातीय उन्माद भड़का कर लोगों में फूट डालने की उन्होंने निन्दा की।

उन्होंने मजदूरों को न्यायोचित न्यूनतम वेतन देने, किसानों का कर्ज माफ करने, कुशल व अकुशल सभी बेरोजगारों को रोजगार देने, महंगाई व बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने, शिक्षा व चिकित्सा के निजीकरण–व्यापारीकरण की योजनाएं वापस लेने, नशाखोरी बन्द करने, प्राइवेट कम्पनियों की लूट का शिकार बनाने वाली फसल बीमा योजना को रद्द कर किसान हितैषी बनाने, मनरेगा स्कीम को चालू करने जैसी मांगों पर चलाये जा रहे आन्दोलन को जोरदार बनाने का आह्वान पार्टी कार्यकर्ताओं से किया।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com

फोन नं. : 011-25726631, 9868350503